EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Nikhil Ranjan
Useful For Prelims
Date: 19 December 2025

भारत-ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले

आर्थिक समझौता द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा देगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) द्विपक्षीय संबंधों को नया विश्वास एवं ऊर्जा प्रदान करेगा और दोनों देशों में वृद्धि के अवसर भी पैदा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आयोजित 'भारत-ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन' में यह बात कही। उन्होंने अपने संबोधन में मांडवी से मस्कट तक दोनों देशों के बीच सदियों पुराने समुद्री व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया जो वर्तमान समय में जीवंत वाणिज्यिक आदान-प्रदान की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के 70 वर्ष पुराने कूटनीतिक संबंध सदियों से निर्मित विश्वास और मित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भारत और ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत वस्त्र, कृषि उत्पाद तथा चमड़े के सामान सहित भारत के 98 फीसद निर्यात को ओमान में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। इसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कहा गया है। सीईपीए को भारत-ओमान के साझा भविष्य की रूपरेखा करार देते हुए प्रधानमंत्री ने व्यापार जगत के लोगों से इस समझौते की पूरी क्षमता का लाभ उठाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) हमारी साझेदारी को 21वीं सदी में नया विश्वास एवं नई ऊर्जा प्रदान करेगा।' उन्होंने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को नई गति देगा, निवेश में नया विश्वास उत्पन्न करेगा और हर क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों, नीतिगत स्थिरता, सुशासन एवं निवेशकों के उच्च विश्वास के दम पर देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा, 'भारत ने पिछले 11 वर्ष में न केवल नीतियों में बदलाव किया है, बल्कि अपने आर्थिक स्वरूप को भी बदल दिया है।'

मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में पिछली तिमाही में भारत की आठ प्रतिशत से अधिक की उच्च वृद्धि इसकी मजबूत प्रकृति और अंतर्निहित शक्तियों को उजागर करती है। उन्होंने कहा, 'भारत की प्रगति हमेशा से साझा प्रगति की कहानी रही है। भारत जब आगे बढ़ता है, तो वह अपने मित्रों को भी अपने विकास में भागीदार बनाता है। हम आज भी यही कर रहे हैं।' प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि भारत की वृद्धि की यात्रा में ओमान के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।

मोदी ने कहा कि भारत विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, लाजिस्टिक, संपर्क, विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलाओं, विनिर्माण क्षमताओं और हरित विकास को विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है ताकि जीवन एवं कारोबार की सुगमता को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने हाल के वर्षों में भारत द्वारा लागू किए गए सुधारों का भी उल्लेख किया जिनमें जीएसटी और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता शामिल हैं। मोदी ने ओमान की कंपनियों को ऊर्जा, तेल एवं गैस, पेट्रोरसायन और उर्वरकों के पारंपरिक क्षेत्रों से परे देखने और हरित ऊर्जा, सौर पार्क, ऊर्जा भंडारण, कृषि-प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया।

मस्कट में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

मैत्री पर्व कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के साथ।

21वीं सदी का भारत त्वरित निर्णय लेता है : प्रधानमंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि 21वीं सदी का भारत बड़े और त्वरित फैसले लेता है, बड़े लक्ष्य तय करके आगे बढ़ता है और समयबद्ध तरीके से परिणाम देता है। दो दिवसीय ओमान यात्रा पर आए मोदी ने यहां भारतीय छात्रों और समुदाय के सदस्यों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। छात्रों और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उत्साहपूर्वक नारे लगाते हुए तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया।

मोदी ने संबोधन के दौरान वहां उपस्थित लोगों को 'लघु-भारत' की संज्ञा दी, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने 'मोदी, मोदी, मोदी' के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने इस अवसर पर भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों की उपस्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि आज हम सब एक परिवार की तरह एकत्र हुए हैं। आज हम अपने देश और टीम इंडिया का उत्सव मना रहे हैं। भारत में, हमारी विविधता हमारी संस्कृति की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, '21वीं सदी का भारत बड़े और त्वरित फैसले लेता है, बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता है और तय समयसीमा के भीतर परिणाम देता है।' मैत्री पर्व कार्यक्रम में भारतीय स्कूलों के 700 से अधिक छात्र भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री मोदी को 'आर्डर आफ ओमान' सम्मान से नवाजा गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान व उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्हें विशिष्ट नागरिक सम्मान 'आर्डर आफ ओमान' से नवाजा।

प्रधानमंत्री मोदी को ओमान की दो दिवसीय यात्रा के दौरान यह सम्मान दिया गया। तीन देशों के अपने दौरे के दौरान मोदी जार्डन और इथियोपिया की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आर्डर आफ ओमान' प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस सम्मान के लिए सुल्तान हैथम बिन तारिक, ओमान सरकार और वहां की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। यह भारत और ओमान के लोगों के बीच स्नेह और विश्वास का प्रतीक है।'

Jansatta Page No-14

बाजार में पहुंच बढ़ाने को भारत ने ओमान से किया मुक्त व्यापार करार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

कठिन भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अपने व्यापार को विस्तार देने के लक्ष्य के साथ भारत ने गुरुवार को ओमान के साथ मुक्त व्यापार करार को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक मौजूदगी में दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए।

समझौते के तहत वस्त्र, कृषि उत्पाद तथा चमड़े के सामान सहित भारत के 98 फीसद निर्यात को ओमान में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की जाएगी। समझौते के तहत वस्त्र, कृषि उत्पाद तथा चमड़े के सामान सहित बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री मोदी को 'आर्डर आफ ओमान' सम्मान से नवाजा गया पेज 14

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को विशिष्ट नागरिक सम्मान 'आर्डर आफ ओमान' से नवाजा गया।

Jansatta Page No-1

चीन की 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' रणनीति के खिलाफ जरूरी है ओमान का सहयोग

भारत-ओमान ने सामुद्रिक सहयोग के लिए दृष्टि प्रपत्र को दी मंजूरी, मोदी व सुल्तान हैथम के बीच द्विपक्षीय वार्ता में बनी सहमति

जयप्रकाश रंजन • जागरण

नई दिल्ली : गुरुवार को भारत और ओमान के बीच सामुद्रिक क्षेत्र में सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिए एक दृष्टि प्रपत्र पर सहमति बनी है। इसे हिंद महासागर व खाड़ी के क्षेत्र में भारत के ऊर्जा व रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उक्त सहमति पीएम नरेन्द्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बनी, जिसकी घोषणा बाद में दोनों देशों की तरफ से की गई। वैसे भी चीन की 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' के खिलाफ ओमान का सहयोग जरूरी है। मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार शाम को ओमान पहुंचे थे।

मोदी की यह ओमान यात्रा भारत और ओमान के बीच कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। उन्होंने सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर बात की। बैठक में मोदी और सुल्तान ने भारत और ओमान के बीच कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने को द्विपक्षीय साझेदारी में एक मील का पत्थर बताया। गुरुवार को ही भारत-ओमान के बीच कांप्रिहेसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) पर हस्ताक्षर किए गए। मोदी ने इस कारोबारी समझौते को दोनों देशों के साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। आशा है कि भारत-ओमान मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होती रहेगी।

पीएम मोदी व सुल्तान हैथम के बीच बैठक में मैरीटाइम सहयोग के लिए एक दृष्टिपत्र पर भी सहमति बनी है। यह प्रपत्र दोनों देशों की समुद्री पड़ोसी के रूप में सदियों पुरानी साझेदारी को मजबूत करते हुए क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनामी और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग की प्रतिबद्धता को बताता है। इस समझौते के जरिए ओमान के पास स्थिति होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भारत अपने हितों की सुरक्षा करना चाहता है। इस स्ट्रेट से विश्व का 20-30 प्रतिशत तेल व्यापार गुजरता है। भारत आने वाले कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा यहां से आता है। भारत को पहले से ओमान के दुक्म पोर्ट में सैन्य और लाजिस्टिक उपयोग की सुविधा मिली हुई है। नया समझौता इस सहयोग को और गहरा करेगा। यह भारतीय नौसेना को पश्चिमी हिंद महासागर में मजबूत आधार प्रदान करता है। दुक्म पोर्ट भारत के लिए एक वैकल्पिक रणनीतिक ठिकाना है। यह चीन की 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' रणनीति (जिसमें पाक के ग्वादर पोर्ट आदि शामिल हैं) का मुकाबला करने में मदद करता है। ओमान गल्फ क्षेत्र का एकमात्र देश है जहां भारतीय सेना की तीनों शाखाएं नियमित संयुक्त अभ्यास करती हैं।

मस्कट में गुरुवार को पीएम नरेन्द्र मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सौंपते पीएम सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद। आइएएनएस

ओमान ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान

प्रथम पृष्ठ से आगे

ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द फर्स्ट क्लास आफ द आर्डर आफ ओमान' प्रदान किया। यह सम्मान मोदी को भारत-ओमान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। इस सम्मान के साथ पीएम मोदी विरले वैश्विक नेता बन गए हैं जिन्हें 29 राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ओमान का ये सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी से पहले नेल्सन मंडेला, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जापान के सम्राट अकिहितो और जार्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय जैसे वैश्विक नेताओं को प्रदान किया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पीएम मोदी की वैश्विक नेतृत्व क्षमता और राजनेता के रूप में स्वीकार्यता का बड़ा प्रमाण बताया है। तीन देशों की इस चार दिवसीय यात्रा के दौरान मोदी को इथियोपिया सरकार ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान' ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से नवाजा था।

पिछले 11 सालों में भारत ने अपना आर्थिक डीएनए बदल दिया : मोदी: एएनआइ के अनुसार, मोदी ने भारत-ओमान बिजनेस समिट को भी संबोधित किया। उन्होंने पिछले 11 सालों में भारत द्वारा शुरू किए गए कई सुधारों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने इसे दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी बाजारों में से एक बना दिया है। मोदी ने कहा- "पिछले 11 सालों में भारत ने न सिर्फ नीतियां बदली हैं, बल्कि अपना आर्थिक डीएनए भी बदल दिया है।" उन्होंने इंसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और जीएसटी जैसी कई पहलों को जिक्र करते हुए कहा कि इनसे विकास की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। उन्होंने ओमानी कंपनियों को भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने का न्योता दिया।

प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के बाद स्वदेश रवाना: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की यात्रा के बाद गुरुवार को ओमान से स्वदेश रवाना हुए। मोदी को ओमान के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मामलों के मंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने 'नमस्ते' करते हुए विदाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यात्रा को दिलों को छूने वाली व संबंधों को मजबूत करने वाली बताया। उन्होंने लिखा कि चर्चाओं व समझौतों के बाद मोदी जार्डन, इथियोपिया व ओमान की यात्रा के बाद भारत प्रस्थान कर रहे हैं।"

प्रोफेशनल्स के लिए दरवाजे खुले, आइटी व हेल्थ सर्विस निर्यात में भी होगी बढ़ोतरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ओमान के साथ कंप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) पर अमल होते ही इंजीनियरिंग, मेडिकल, आइटी, शिक्षा व निर्माण से जुड़े भारतीय प्रोफेशनल्स अब ओमान में आसानी से अपनी सेवा दे सकेंगे। अब अनुबंध सेवा के तहत वे चार साल तक ओमान में रह सकेंगे। वैसे कोई भी प्रोफेशनल्स 180 दिनों तक ओमान में रहकर स्वतंत्र रूप से सेवा दे सकेगा। बिजनेस के नाम पर भी ओमान भारतीय को 90 दिनों का वीजा देगा। ओमान में चलने वाली भारतीय कंपनियों में अब 50 प्रतिशत तक भारतीय काम कर सकेंगे। पहले यह सीमा 20 प्रतिशत थी। सीपा होने से आइटी, हेल्थ, शिक्षा, अनुसंधान, आडियो-वीडियो व टूरिज्म जैसे सर्विस सेक्टर के निर्यात में इजाफा होगा। सर्विस सेक्टर में ओमान सालाना 12.52 अरब डालर का आयात करता है, इनमें भारत की हिस्सेदारी 5.31 प्रतिशत है।

मध्य पूर्व व आफ्रीकी देशों में निर्यात बढ़ाने का मिलेगा मौका: फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष एससी रल्हन ने बताया कि गल्फ को-आपरेशन काउंसिल (जीसीसी) का सदस्य देश होने व अफ्रीका के पास होने से मध्य पूर्व व अफ्रीका में भारत को अपना निर्यात बढ़ाने में मौका मिलेगा। भारतीय निर्यातक ओमान में अपना केंद्र खोलकर वैल्यू एडीशन करके वहां से मध्य पूर्व व अफ्रीकी देशों में निर्यात कर सकेंगे।

निर्यात की भरपाई में भी मिलेगी मदद: ओमान के साथ सीपा होने से अमेरिकी शुल्क से प्रभावित होने वाले निर्यात की भरपाई में मदद मिलेगी। अमेरिका की तरफ से 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के बाद टेक्सटाइल, समुद्री उत्पाद, लेदर, जेम्स व ज्वैलरी जैसे आइटम के निर्यात की बढ़ोतरी दर प्रभावित हुई है। ओमान इन वस्तुओं का बड़ा आयातक देश हैं।

> भारत व ओमान के संबंधों के लिए सीपा ऐतिहासिक कदम है जिसके सकारात्मक परिणाम आने वाले दशकों में दिखेंगे। सीपा से व्यापार, निवेश एवं नए अवसर मिलेंगे व युवाओं को लाभ मिलेगा। **- नरेन्द्र मोदी, पीएम।**

> ओमान के साथ सीपा से भारतीय निर्यातक व प्रोफेशनल्स को ओमान के बाजार में अवसर मिलेंगे। सीपा के तहत राष्ट्र हित का ध्यान रखा गया है, वहीं, इससे सरकार की प्रतिबद्धता के मुताबिक भारतीय किसान, कारीगर, एमएसएमई लाभान्वित होंगे। **- पीयूष गोयल, वाणिज्य व उद्योग मंत्री**

Dainik Jagaran Page No-11

फैसला : अधिकांश भारतीय उत्पादों पर ओमान में कोई शुल्क नहीं लगेगा

मस्कट, एजेंसी। भारत और ओमान ने गुरुवार को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत कपड़ों और कृषि उत्पाद सहित भारत के 98% सामान पर ओमान में शुल्क नहीं लगेगा। भारत खजूर, पेट्रो रसायन वस्तुओं और संगमरमर जैसे ओमान के उत्पादों पर शुल्क कम करेगा।

समझौते के 2026-27 की पहली तिमाही से लागू होने की उम्मीद है। करार पर हस्ताक्षर के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक मौजूद रहे। भारत ने डेयरी एवं कृषि उत्पाद, सोने-चांदी के आभूषण और खेल आदि पर छूट नहीं दी।

सम्मान: पीएम नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने गुरुवार को देश के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित किया। • प्रेट्र

98 भारतीय सामान पर ओमान में शुल्क नहीं लगेगा

नीतियों में व्यापक बदलाव

मोदी ने कहा कि भारत का विकास होता है, तो उसके मित्र देशों को भी विकास में मदद मिलती है। भारत, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह पूरी [illegible] फायदेमंद है। ओमान के लिए यह और अधिक फायदेमंद है, क्योंकि घनिष्ठ मित्र होने के साथ हम एक-दूसरे के बाजारों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। भारत ने पिछले 11 वर्ष में भारत ने न केवल नीतियों में बदलाव किया है, बल्कि अपने आर्थिक स्वरूप को भी बदल दिया है।

निवेश और रोजगार के अवसर खुलेंगे

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत-ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर से खाड़ी क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भागीदारी मजबूत होगी।

इसके साथ ही दोनों पक्षों के लिए [illegible] के क्षेत्र में बड़े अवसर पैदा करेगा। निर्यात के लिहाज से देखा जाए तो भारत के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। यह बीते 6 महीनों में भारत का दूसरा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। इससे पहले ब्रिटेन के साथ भारत ने एफटीए किया है। बता दें, ओमान में करीब सात लाख भारतीय रहते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार 10 अरब डॉलर से अधिक है। यह समझौता व्यापार, निवेश, रोजगार और सप्लाई चेन को नई गति देगा।

Dainik Jagaran Page No-14

समझौते में आयुष और पारंपरिक चिकित्सा को शामिल किया गया है। यह पहली बार है, जब किसी व्यापार समझौते में आयुष चिकित्सा जुड़ी है।

नौकरियां बढ़ेंगी : ओमान ने पहली बार सेवाओं के क्षेत्र में 127 उप-क्षेत्रों को खोला है। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं को बड़े अवसर मिलेंगे। इससे उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा होंगी।

संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा समझौता : मोदी

मस्कट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) द्विपक्षीय संबंधों को नया विश्वास एवं ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित भारत-ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन में कहा कि यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नई दिशा देगा। उन्होंने कहा, आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, जिसकी गूंज कई दशकों तक सुनाई देगी।

Hindustan Page No-21

दुखद | पद्मश्री, पद्म भूषण समेत कई पुरस्कार मिले, राष्ट्र के गौरव को जीवंत करने वाले कलाकार थे, अपना स्टूडियो नोएडा में बनाया और वर्ष 1990 से वह यहीं रह रहे थे

राम सुतार ने पटना में गांधीजी और कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमाएं बनाईं

स्मृति शेष

निशांत कौशिक

नोएडा। महाराष्ट्र के धुलिया जिले के गोंडूर गांव में 19 फरवरी 1925 को जन्मे विख्यात मूर्तिकार राम वी सुतार ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने समेत कई प्रतिमाएं और मूर्तियां बनाईं। संसद परिसर में ध्यान में बैठे हुए महात्मा गांधी और घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाएं भी उनकी ही देन हैं। राम सुतार राष्ट्र के गौरव को जीवंत करने वाले कलाकार थे। महाराष्ट्र में बुनियादी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बॉम्बे के सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। 1953 में उन्होंने मॉडलिंग के लिए प्रतिष्ठित मेयो गोल्ड मेडल जीता। वर्ष 1954 से 1958 के बीच सुतार ने औरंगाबाद स्थित पुरातत्व विभाग में कार्य किया। उन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाओं की कई प्राचीन मूर्तियों के जीर्णोद्धार में भूमिका निभाई। 1959 में सरकारी नौकरी छोड़ पूर्णकालिक पेशेवर मूर्तिकार बन गए। स्टूडियो नोएडा में बनाया और वर्ष 1990 से वह यहीं रह रहे थे। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण समेत कई पुरस्कार मिले।

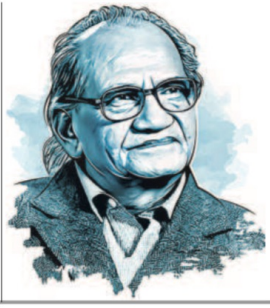

सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी शिल्पकार

182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी राम सुतार ने डिजाइन किया

- संसद भवन में गांधीजी की प्रतिमा
- बेंगलुरु में भगवान शिव की प्रतिमा
- अयोध्या की पहचान लता मंगेशकर चौक पर लगी वीणा
- पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की दो बच्चों के साथ लगी प्रतिमा
- बिहार विधानसभा परिसर में एएन सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमाएं

> राम सुतार के योगदान ने कलात्मक-सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। उनकी कृतियां भारत की चिरस्थायी विरासत के प्रतीक हैं। **- द्रौपदी मुर्मु,** राष्ट्रपति

> राम सुतार अद्वितीय थे। उनकी कलाकृतियां हमेशा भारत के इतिहास, संस्कृति और सामूहिक भावना की शक्तिशाली अभिव्यक्तियां बनी रहेंगी। **-नरेंद्र मोदी,** प्रधानमंत्री

Hindustan Page No-21

उत्साह

दोहा : फीफा अंतरमहाद्वीपीय कप के फाइनल में फ्लेमेंगो को हराकर ट्राफी के साथ जश्न मनाते पेरिस सेंट-जर्मेन के खिलाड़ी।

Dainik Jagaran Page No-9

Jansatta Page No-22

बैठक

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वान वील ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा उपकरणों के 'सह-विकास और सह-उत्पादन' के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों समेत कई द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की।

Jansatta Page No-14

प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक लोस में पेश

स्थायी समिति में भेजने का फैसला अध्यक्ष पर छोड़ा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 पेश गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया। यह प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेकर आई थी। इस प्रस्ताव का विपक्ष के सांसदों ने विरोध किया और अभी तक यह प्रस्ताव सदस्यों को उपलब्ध भी नहीं कराया गया है।

पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने इस विधेयक को सदन में पेश करने की अनुमति दी और इसे मंत्री ने पटल पर पेश किया। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सरकार इस विधेयक को स्थायी समिति भेजने का प्रस्ताव लाई थी, जिस पर

सीतारमण ने विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 का उद्देश्य प्रावधानों को मिलाकर एक एकीकृत संहिता बनाना है।

सभापति ने कहा कि इस पर आखिरी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। द्रमुक सांसद अरुण नेहरू ने सदन में विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बिगाड़ेगा। वहीं कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक तरीके से विधायिका तथा कार्यपालिका के अधिकार, जांच संबंधी और अर्द्धन्यायिक शक्तियां एक ही बोर्ड को देगा।

सीतारमण ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक पेश किए जाते समय इन बिंदुओं को उठाने की जरूरत नहीं है और सरकार इसे संसद की स्थायी समिति को भेजना का प्रस्ताव रख रही है, इसलिए इन पर वहीं विचार-विमर्श होना चाहिए।

सेबी निदेशक मंडल में 15 सदस्यों का प्रावधान

इस क्रम में सेबी के निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या नौ से बढ़ाकर 15 करने का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक का मकसद किसी भी अधीनस्थ कानून को पारदर्शी और परामर्श आधारित प्रक्रिया से लागू करना है। विधेयक में पूंजी बाजार नियामक सेबी के बोर्ड सदस्य को हटाए जाने का नया आधार भी जोड़ा गया है। अगर सदस्य ने कोई वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो जो उसके कर्तव्यों पर प्रभाव डाल सकता है तो उसे हटाने का प्रावधान किया गया है।

Jansatta Page No-21

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को दी जानकारी | खतरा | चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर भारत

वर्ष 2040 तक कैंसर रोगियों की संख्या 20 लाख

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि दुनिया भर में कैंसर मामलों में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है और 2040 तक देश में कैंसर के मामलों की संख्या लगभग 20 लाख हो सकती है।

सिंह ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने महिलाओं में गर्भाशय (सर्वाइकल) कैंसर के उपचार के लिए पहली बार एचपीवी वैक्सीन विकसित की है और सरकार इसे किफायती दर पर या मुफ्त में अधिक बड़ी आबादी तक उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि पूरी

राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सच है कि पूरी दुनिया में कैंसर के मामले बढ़े हैं। अगर आप वैश्विक आंकड़े देखें तो हर साल दुनिया में दो करोड़ कैंसर रोगी होते हैं, यानी हर साल लगभग दो करोड़ कैंसर मरीज। भारत में ही हमारे पास लगभग 14 से 15 लाख, यानी करीब 15 लाख मामले हैं। सिंह ने कहा कि यह आंकड़ा 2040 तक बढ़कर लगभग 20 लाख होने का अनुमान है।

दुनिया में कैंसर के मामले बढ़े हैं। अगर आप वैश्विक आंकड़े देखें तो हर साल दुनिया में दो करोड़ कैंसर रोगी होते हैं, यानी हर साल लगभग दो करोड़ कैंसर मरीज। भारत में ही हमारे पास लगभग 14 से 15 लाख, यानी करीब 15 लाख मामले हैं। सिंह ने कहा कि यह आंकड़ा 2040 तक बढ़कर लगभग 20 लाख होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कैंसर की व्यापकता के लिहाज से भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिसमें देश के भीतर बीमारियों के स्वरूप में बदलाव होना शामिल है। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक तक भारत संक्रामक रोगों से ग्रस्त था, इसके बाद गैर-संक्रामक रोगों का दौर आया। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में भारत दोनों से प्रभावित हैं।

उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि इनमें से कैंसर सहित कई बीमारियां, जो जीवन के उत्तरार्द्ध के दशकों में होती थीं, अब प्रारंभिक दशकों में हो रही हैं। जो कैंसर पहले अधिक उम्र में होता था, वह अब कम उम्र में भी हो सकता है। यही स्थिति हार्ट अटैक की भी है, जो पहले जीवन के बाद के चरण में होते थे, अब कम उम्र में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही समाज को इस बात पर गर्व है कि भारत की 70 फीसद आबादी 40 वर्ष से कम उम्र की है, लेकिन सच्चाई का दूसरा पहलू यह भी है कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों की संख्या भी बढ़ी है, और इससे रोगों का बोझ भी बढ़ता है। उपचार के संबंध में मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के लगभग हर जिला अस्पताल में कैंसर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है।

Jansatta Page No-10

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का मामला

विधेयक 'शांति' को संसद में मिली मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

संसद ने गुरुवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की इजाजत संबंधी प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्यसभा ने 'भारत के रुपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025 को चर्चा और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। उच्च सदन ने विपक्षी सदस्यों की ओर से पेश किए तमाम संशोधनों को भी ध्वनिमत से खारिज कर दिया। एक दिन पहले ही लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया।

राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विधेयक को एतिहासिक

विपक्ष ने इस विधेयक में आपूर्तिकर्ता के उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा, यह संवेदनशील क्षेत्र में निजी कारपोरेट समूहों के लिए रास्ता खोलने वाला है।

और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य हासिल करने में अहम करार दिया। उधर, विपक्ष ने इस विधेयक में आपूर्तिकर्ता के उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा, यह संवेदनशील क्षेत्र में निजी कारपोरेट समूहों के लिए रास्ता खोलने वाला है।

चर्चा के जवाब में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो पहले भी थे। लेकिन, सत्तापक्ष का विरोध करते हुए विपक्षी सदस्य, अपने समय के प्रावधानों का ही विरोध कर देते हैं। उन्होंने कहा, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए 37 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। मंत्री ने कहा, अगर हमने 2047 तक 100 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य रखा है तो पूरा करने में परमाणु क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सिंह ने कहा, मौजूदा दौर में दुनिया में अलग-थलग रहने का दौर खत्म हो चुका है।

उन्होंने कहा कि उन्हीं सुरक्षा उपायों को जारी रखा गया है जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय अपनाए गए थे। सिंह ने यह भी कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी, लेकिन सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया गया है। मंत्री ने कहा कि नुकसान की स्थिति में संचालक को भरपाई करनी होगी और परमाणु उत्तरदायित्व कोष होगा। उन्होंने कहा, अब दूसरे देश, भारत का अनुसरण करते हैं।

Jansatta Page No-8

रोजगार की राह

देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर आबादी के लिए रोजी-रोटी का इंतजाम एक बड़ी चुनौती रही है। लंबे समय तक इस समस्या के बने रहने का नतीजा यह हुआ कि विकास एक तरह से विभाजित रहा और एक बड़ा तबका मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिशों से भी वंचित रहा। मगर जब से गारंटी के रूप में ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराने की पहल हुई है, उसके बाद से एक बड़ा फर्क दर्ज किया गया। करीब बीस वर्ष पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा लागू हुआ, तो उसके तहत वर्ष में सौ दिन काम की व्यवस्था से गांव-देहात में रहने वाले परिवारों के सशक्तीकरण में उल्लेखनीय मदद मिली। मनरेगा की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई बार इसे दुनिया भर में एक सीखने लायक कार्यक्रम के तौर पर भी देखा गया। अब केंद्र सरकार ने मनरेगा का रूप बदल कर उसका नाम 'विकसित भारत-रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'बीवी- जी राम जी' रखा है और उसमें अब कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया।

गौरतलब है कि नई प्रस्तावित व्यवस्था मनरेगा का ही नया स्वरूप होगी, जिसमें ग्रामीण परिवार को सौ दिन के बजाय एक सौ पच्चीस दिनों के रोजगार की गारंटी की बात की गई है। इसके अलावा, खर्च वहन करने, पारिश्रमिक भुगतान और खेती के दिनों के संदर्भ में नए प्रावधानों की वजह से इस योजना के किसानों और मजदूरों, दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने की उम्मीद की जा रही है। मनरेगा के तहत जिन लोगों को काम मिलता है, उनकी मजदूरी का लगभग पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती रही है, जबकि सामान आदि का खर्च एक निश्चित अनुपात में राज्य सरकारें उठाती हैं। अब कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़ कर 'बीवी- जी राम जी' के तहत होने वाले कुल खर्च का साठ फीसद केंद्र सरकार वहन करेगी और चालीस फीसद राज्य सरकारें उठाएंगी। इस योजना के अंतर्गत खेतों में बुआई और कटाई के मौसम में साठ दिनों के दौरान मजदूरों को काम नहीं मिल सकेगा, ताकि खेती-किसानी के काम के लिए मजदूरों की कमी न हो। इसके अलावा, इस काम में भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए मजदूरी के भुगतान में बायोमेट्रिक और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाएगी।

जाहिर है, बदलावों के बाद अगर रोजगार गारंटी की व्यवस्था ग्रामीण इलाकों के मजदूरों के लिए सहायक सिद्ध हुई, तो बेशक इसे एक सकारात्मक कदम माना जाएगा। देश की ग्रामीण आबादी के हित में प्रथम दृष्टया यह योजना एक बेहतर पहल लगती है, लेकिन इस संदर्भ में विपक्षी दलों की ओर से कई आशंकाएं भी जताई गई हैं। अगर ग्रामीण इलाकों में काम करने की जगह तय करने से लेकर अन्य मामलों में यह योजना केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और उसकी शर्तों पर आधारित होगी, तो खर्च का जिम्मा राज्यों पर आएगा। ऐसे में इसके नतीजे घोषित दावों के मुकाबले उलट भी आ सकते हैं और इसका काम के अधिकार पर विपरीत असर पड़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी लागू होने के बाद से मनरेगा की अहमियत छिपी नहीं रही है। खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान जब देश भर में गरीब तबकों के लोग भयावह अभाव से जूझ रहे थे, तब मनरेगा उनके लिए जीवन-रेखा साबित हुआ। ऐसे में यह देखने की बात होगी कि नए स्वरूप में ग्रामीण इलाकों के गरीब तबकों के लिए रोजगार गारंटी की नई व्यवस्था कितनी सहायक साबित होगी।

झारखंड की लेडी टार्जन कही जाती हैं जमुना टुडू

जमुना टुडू का जन्म 1980 में आज ही ओडिशा में हुआ था। 1998 में शादी के बाद झारखंड के मुतुरखाम गांव गईं और वहां वन माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ काटने की स्थिति देखी। इस दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया। परिवार के विरोध के बावजूद, उन्होंने गांव की महिलाओं को एकजुट कर वन सुरक्षा समिति का गठन किया। इस समिति ने अवैध कटाई के खिलाफ संघर्ष किया, जिसमें उन्हें कई बार जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ा। फिर भी, जमुना ने हार नहीं मानी और उन्होंने 50 हेक्टेयर जंगल को विनाश से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Dainik Jagaran Page No-14

सेना ने गोवा, दमन व दीव को पुर्तगाल से मुक्त कराया

1961 में आज ही आपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने गोवा, दमन व दीव को पुर्तगाल से मुक्त कराया था। पुर्तगाल ने वर्ष 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। शुरुआत में केंद्रशासित प्रदेश रहने के बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।

बलिदान हुए बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां व रोशन सिंह

1927 में आज ही महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को अंग्रेजों ने अलग-अलग जेलों में फांसी दे दी थी। तीनों क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

Dainik Jagaran Page No-14

छोटी आंत से माइक्रोबियल सैंपल लेने को डिवाइस तैयार

आइआइटी-एम्स की उपलब्धि ▶ छोटी आंत से सीधे ले सकेगी बैक्टीरिया के नमूने, समय और लागत में बचत

आंतों, मेटाबालिज्म और पोषण से जुड़ी बीमारियों की पहचान में होगी मददगार

अनूप कुमार सिंह • जागरण

नई दिल्ली : आइआइटी व एम्स दिल्ली के विज्ञानियों ने एक ऐसी निगलने योग्य कैप्सूल आकार की माइक्रोडिवाइस तैयार की है, जो सीधे मानव शरीर की छोटी आंत से बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों के नमूने एकत्र करने में सक्षम है। इसे मानव माइक्रोबायोम को समझने और आंतों से जुड़ी बीमारियों के शुरुआती निदान की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस माइक्रोडिवाइस को मरीज आसानी से निगल सकता है। छोटी आंत में पहुंचने पर यह सक्रिय होकर वहां मौजूद बैक्टीरिया व जैविक तत्वों का नमूना अपने भीतर संग्रहित कर लेती है। इसके बाद यह खुद को सील कर लेती है, ताकि आंत के अलग-अलग हिस्सों के सूक्ष्मजीव आपस में न मिलें। विशेषज्ञों के अनुसार यह डिवाइस आंतों, मेटाबालिज्म और पोषण से जुड़ी बीमारियों की पहचान में मददगार होगी।

आइआइटी दिल्ली की मेडिकल माइक्रोडिवाइस एंड मेडिसिन प्रयोगशाला के प्रधान विज्ञानी प्रोफेसर सर्वेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मानव शरीर के भीतर सूक्ष्मजीवों की एक विशाल दुनिया है, जो पाचन, प्रतिरक्षा और कई बीमारियों में अहम भूमिका निभाते हैं। अब तक छोटी आंत के माइक्रोबायोम का अध्ययन करना कठिन था, क्योंकि इसके लिए एंडोस्कोपी जैसी जटिल प्रक्रियाओं या फिर मल के नमूनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो सटीक जानकारी नहीं देते थे। नई माइक्रोडिवाइस इस कमी को दूर करेगी।

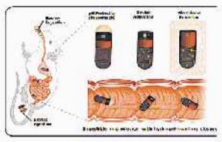

डिवाइस की छोटी आंत से बैक्टीरिया के नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया व चूहे पर इसके व्यवहार को दर्शाता रेखाचित्र: सौजन्य- आइआइटी

एम्स नई दिल्ली के गैस्ट्रोएंटरोलाजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन यूनिट के को-सीनियर विज्ञानी डा. समग्र अग्रवाल ने बताया कि छोटी आंत स्वास्थ्य और बीमारी दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस डिवाइस के आ जाने से छोटी आंत में मौजूद माइक्रोब्स और रासायनिक तत्वों की सही जानकारी मिल सकेगी, जिससे बीमारियों का जल्दी पता लगाना, पुरानी बीमारियों की निगरानी करना व अधिक असरदार उपचार विकसित करना संभव होगा। उन्होंने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने इस शोध को वित्तपोषित किया है। यह शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल स्माल में 'ए स्माल पिल-लाइक इन्जेस्टिबल माइक्रोडिवाइस फार साइट-स्पेसिफिक माइक्रोबायोम सैंपलिंग इन द अपर जीआइ ट्रैक्ट' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अब नियामक मंजूरियों के बाद इसे क्लिनिकल उपयोग में लाने की तैयारी है, जिससे आने वाले समय में मरीजों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।

कैसे आती है बाहर : छोटी आंत में पाचन के दौरान भोजन आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक लहरनुमा गति 'पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट' इसे धीरे-धीरे आगे की ओर धकेलता है। जिससे यह छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचती है। पाचन तंत्र के सामान्य मार्ग से आगे यह डिवाइस मल त्याग से बिना दर्द या अतिरिक्त बल के शरीर से बाहर आ जाती है। इसे ऐसे तैयार किया गया है कि इसे बाहर आने के बाद आसानी से पहचाना व निकाला जा सके।

नियंत्रित रिकवरी : मरीज को पहले से बताया जाता है कि 24-72 घंटे के भीतर मल त्याग के दौरान यह निकलेगी। इसके बाद मल को विशेष स्टूल-कलेक्शन किट में एकत्र किया जाता है। इसकी सतह चिकनी और अलग रंग की होती है जो कि पहचानी जा सकती है।

Dainik Jagaran Page No-14

भारत को एआइ व आपूर्ति शृंखला के लिए रणनीतिक साझेदार मानता है अमेरिका

- अमेरिकी अधिकारी ने राजनीतिक तनाव के कारण भारत के वाशिंगटन में हुए पैक्स शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने की बात को किया खारिज
- अमेरिकी आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा, वे फरवरी में होने वाले भारत एआइ इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका आर्टिफिशिय इंटेलिजेंस (एआइ) और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने के प्रयासों में भारत को महत्वपूर्ण संभावित भागीदार मानता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने यह बात कही है, साथ ही उन्होंने उन बातों को खारिज कर दिया है कि राजनीतिक तनाव के कारण भारत ने हाल ही में वाशिंगटन में हुए शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया।

अमेरिकी आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने घोषणा की कि वे फरवरी में होने वाले भारत एआइ इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वाशिंगटन में बुधवार को आयोजित पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में पत्रकारों से बात करते हुए हेलबर्ग ने इस सम्मेलन में भारत की अनुपस्थिति से संबंधित सवालों के जवाब दिए। इस सम्मेलन में तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने एआइ अवसंरचना और सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखलाओं पर रणनीति समन्वय स्थापित करने के लिए भाग लिया था। हेलबर्ग ने कहा, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि व्यापार समझौतों से संबंधित अमेरिका और भारत के बीच की बातचीत आपूर्ति शृंखला सुरक्षा पर हमारी चर्चाओं से पूरी तरह से अलग और समानांतर है। हम इन दोनों को एक नहीं मान रहे हैं।'' उन्होंने जोर दिया कि राजनयिक मतभेदों के कारण भारत को शिखर सम्मेलन से बाहर नहीं रखा गया है, बल्कि वर्तमान में वह बहुपक्षीय ढांचे के बजाय द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

Dainik Jagaran Page No-11

आस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर शूटर को पकड़ने में भारतवंशी ने की थी मदद

मेलबर्न, प्रेट्र: आस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर रविवार को हनुक्का उत्सव मनाने के दौरान यहूदियों पर आतंकी हमला हुआ था। दो शूटरों में से एक को पकड़ने में मदद करने वाले भारतीय मूल के 34 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि वह एक हमलावर को मार गिराना चाहते थे और जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते थे।

बीते रविवार को पिता-पुत्र साजिद अकरम और नवीद अकरम ने बोंडी बीच पर यहूदियों पर हमला किया था। इसमें 15 लोगों की मौत हुई थी और 40 लोग घायल हुए, जिनमें भारतीय छात्र भी हैं। सिडनी निवासी 50 वर्षीय साजिद को मार गिराया गया था, जबकि आस्ट्रेलिया में जन्मा उसका 24 वर्षीय बेटा नवीद घायल हो गया। दोनों हमलावर इस्लामिक स्टेट (आइसिस) से प्रेरित थे। उन्होंने नवंबर में फिलीपींस की यात्रा भी की थी। साजिद ने भारत के पासपोर्ट पर और नवीद ने आस्ट्रेलिया के

- अमनदीप सिंह ने कहा, वह हमलावर को मार गिराना चाहते थे
- रविवार को यहूदियों पर हुए हमले में 15 लोगों की गई थी जान

अमनदीप सिंह बोला। फाइल

पासपोर्ट पर यह यात्रा की थी। एसबीएस न्यूज के अनुसार, भारतीय और न्यूजीलैंड मूल के माता-पिता के बेटे अमनदीप सिंह बोला ने साजिद को काबू करने में मदद की थी। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की मदद से उसे काबू किया था। उन्होंने कहा, 'मैं (शूटर पर) कूद पड़ा और उसके हाथ पकड़ लिए। पुलिस अधिकारी की मदद की और कहा कि उसे छोड़ना नहीं।' घटना के समय वह कबाब खा रहे थे। शुरू में गोलीबारी की आवाज को पटाखे की आवाज समझा था।

नफरती भाषण से निपटने को नया कानून बनाएगा आस्ट्रेलिया: रायटर के अनुसार, यहूदियों पर हमले के बाद आस्ट्रेलियाई सरकार नफरती भाषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गुरुवार को नफरती भाषण से निपटने के लिए नया कानून बनाने का वादा किया। उन्होंने बताया कि सरकार ऐसा कानून बनाने का प्रयास करेगी, जिससे नफरती भाषण और हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ आरोप लगाना आसान हो जाएगा। ऐसे मामले में दंड बढ़ाने के साथ ही बीजा रद करना या अस्वीकार करना आसान किया जाएगा। उन संगठनों को निशाना बनाने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसके नेता नफरती भाषण में लिप्त रहते हैं।

Dainik Jagaran Page No-11

सुविधा | देश को कई योजनाओं में अपना मॉडल दे चुके बिहार ने इस वर्ष पुल निर्माण में भी कीर्तिमान रचा, औंटा-सिमरिया छह लेन पुल देश का सबसे चौड़ा पुल इस वर्ष हुआ चालू

कीर्तिमान : बिहार ने देश को दिया नदी पर सबसे चौड़ा पुल

अलविदा 2025

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। देश को कई योजनाओं में अपना मॉडल दे चुके बिहार ने इस वर्ष पुल निर्माण में भी कीर्तिमान रचा। पटना और बेगूसराय के बीच गंगा नदी पर बने औंटा-सिमरिया छह लेन पुल इस वर्ष 22 अगस्त को चालू हो गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संयुक्त रूप से इस पुल का उद्घाटन किया था। इस पुल की खासियत यह है कि यह पुल छह लेन होने के साथ ही देश का सबसे चौड़ा पुल भी है। आम तौर पर छह लेन पुल की चौड़ाई 29.5 मीटर होती है। लेकिन बिहार में बने औंटा-सिमरिया पुल की चौड़ाई 34 मीटर है। देश के सबसे अधिक चौड़े इस पुल पर अधिक संख्या में वाहन आ-जा सकेंगे। यह एक्सपेंशन केबल ब्रिज है। ऐसे में इस पुल के नीचे से मालवाहक जहाजों का परिचालन भी आसानी से हो सकेगा। यह 18 पिलरों पर आधारित है। दोनों ओर 3-3 लेन की सड़क है। औंटा की ओर 100 मीटर चौड़ा रोटरी (जीरो माइल) तथा सिमरिया की ओर 80 मीटर चौड़ा रोटरी बनाकर उसे पार्क का स्वरूप दिया गया है। इस पुल के बनने से दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार के जिलों में बालू, गिट्टी सहित अन्य निर्माण व खाद्य सामग्री को लाना-ले जाना आसान हो गया। नया पुल उत्तर बिहार (बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, अररिया आदि) और दक्षिण बिहार (पटना, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय आदि) के बीच यात्रा करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किमी तक की दूरी कम कर दिया। यह पुल प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिमरिया धाम, जो प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मस्थान भी है, उसे बेहतर संपर्क प्रदान कर रहा है। दूरी और समय कम लगने के कारण लोगों को अधिक पैसे देने पड़ रहे थे। औंटा-सिमरिया पुल के कारण अब दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार के लोगों को कम पैसे में ही आवश्यक सामान मिल रहे हैं। इसके निर्माण पर 1871 करोड़ खर्च हुए हैं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरा की जनसभा में बिहार के लिए घोषित सवा लाख करोड़ के विशेष पैकेज में औंटा-सिमरिया पुल की घोषणा की थी।

22 अगस्त को पीएम नरेन्द्र मोदी ने पुल का किया था औपचारिक उद्घाटन

34 मीटर है औंटा-सिमरिया एक्सपेंशन केबल पुल की चौड़ाई

18 पिलरों पर आधारित पुल पर 1871 करोड़ खर्च हुए हुए हैं

बेगूसराय के बीच गंगा नदी पर बना औंटा-सिमरिया छह लेन पुल।

कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल हुआ पूरा

गंगा नदी पर पटना जिले में कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच छह लेन पुल बन रहा है। इस वर्ष इसका पहला स्ट्रेच कच्ची दरगाह से राघोपुर के बीच बनकर तैयार हो गया। पटना से सटे होने के बावजूद घंटों में पटना पहुंचने वाले राघोपुर निवासी अब महज पांच-सात मिनट में ही पटना आ-जा रहे हैं। यह पहला स्थायी पुल है जो राघोपुर को राजधानी पटना से जोड़ा। लगभग 19 किमी लंबी इस परियोजना में 9.76 किमी का हिस्सा गंगा नदी पर बना एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज है। इसकी चौड़ाई 32 मीटर है।

पटना-गया-डोभी का काम भी हुआ पूरा

लगभग एक दशक से पटना-गया-डोभी चार लेन सड़क का काम चल रहा था। यह इस वर्ष बनकर तैयार हो जाने से लोग पटना से गया अधिकतम दो घंटे में आ-जा रहे हैं। इसी तरह गोपालगंज एलिवेटेड, बख्तियारपुर-मोकामा और परिया-मोहनिया चार लेन सड़क का काम भी इसी वर्ष बनकर पूरा हुआ।

Hindustan Page No-2

अब एआइ से मिलेगी असीमित स्वच्छ ऊर्जा

न्यूक्लियर फ्यूजन में विज्ञानियों को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिससे दुनिया असीमित स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने की दिशा में और करीब पहुंच गई है। ब्रिटेन और आस्ट्रिया के विज्ञानियों ने एक नया एआइ उपकरण गाइरोस्विन विकसित किया है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अत्यधिक गर्म प्लाज्मा को सिमुलेट कर सकता है। यह उपकरण उन गणनाओं को कुछ ही सेकेंड में पूरा कर लेता है, जिन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटरों को भी पूरा करने में कई दिन लगते हैं।

अनिश्चित काल तक फ्यूजन बनाए रखने में मिलेगी मदद

समस्या यह है कि फ्यूजन रिएक्टरों में अत्यधिक गर्म प्लाज्मा टरबुलेंस नामक प्रक्रिया में उछलता रहता है। टरबुलेंस के कारण प्लाज्मा अपने चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, जिससे फ्यूजन प्रतिक्रिया की क्षमता कम हो जाती है। वर्तमान में फ्यूजन प्रतिक्रिया का रिकार्ड वेंडेलस्टीन 7-एक्स फ्यूजन उपकरण के पास है, जिसने 43 सेकेंड तक फ्यूजन बनाए रखा। फ्यूजन प्रतिक्रिया को अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए, विज्ञानियों को विभिन्न परिस्थितियों में टरबुलेंस के निर्माण की अत्यंत सटीक सिमुलेशन की आवश्यकता होती है। गाइरोस्विन रिएक्टरों को अनिश्चित काल तक फ्यूजन बनाए रखने में मदद कर सकता है।

सूर्य की नकल करते हैं फ्यूजन रिएक्टर

न्यूक्लियर फ्यूजन में स्वच्छ ऊर्जा का लगभग अनंत स्रोत बनाने की क्षमता है। इसमें केवल दो प्रकार के हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम की आवश्यकता होती है, जबकि एकमात्र उप-उत्पाद हीलियम है। इसका मतलब है कि इससे न तो लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी कचरे के ढेर बनेंगे और न ही ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होगा जिससे पृथ्वी को नुकसान पहुंचे। फ्यूजन रिएक्टर सूर्य के केंद्र में होने वाली प्रक्रियाओं की नकल करते हैं, जहां हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराकर हीलियम में परिवर्तित होते हैं। हालांकि, पृथ्वी पर एक लघु तारा बनाने के लिए प्लाज्मा को लगभग 10 करोड़ सेंटीग्रेड तक गर्म करना और फ्यूजन के लिए इसे पर्याप्त गर्म और सघन बनाए रखना आवश्यक है। चूंकि कोई भी पदार्थ इतने अधिक तापमान को सहन नहीं कर सकता, इसलिए विज्ञानी टोकामाक नामक अंगूठी के आकार के उपकरण का उपयोग करके प्लाज्मा को चुंबकीय पिंजरे में फंसा लेते हैं। हालांकि, प्लाज्मा अशांत होने के कारण समय के साथ पिंजरे से बाहर निकलने लगता है। गाइरोस्विन के सिमुलेशन की मदद से, इंजीनियर इन चुंबकीय क्षेत्रों को सटीक रूप से समायोजित करके एक स्थिर फ्यूजन प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकेंगे।

दिनों में नही, सेकेंडों में होगी गणना

वर्तमान में सर्वोत्तम सिमुलेशन प्लाज्मा के कणों को सुपरकंप्यूटरों पर पांच आयामों में ट्रैक करते हैं, लेकिन इन सिमुलेशन को पूरा होने में कई दिन लगते हैं। गाइरोस्विन सिमुलेशन के परिणाम के बारे में दिनों के बजाय सेकेंडों में बता सकता है। विज्ञानियों ने कहा कि इस प्रकार के 'एआइ सरोगेट माडल' नए नहीं हैं, लेकिन गाइरोस्विन की सबसे रोमांचक बात इसकी सटीकता है। यह पहला माडल है जो वास्तव में प्लाज्मा टरबुलेंस पर माडल करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि माडल पहले से ही प्लाज्मा टरबुलेंस की अंतर्निहित भौतिकी को समझने के संकेत दिखाने लगा है। हालांकि गाइरोस्विन को अपने प्रशिक्षण में सुधार जारी रखने के लिए कुछ पारंपरिक सिमुलेशन की आवश्यकता होगी। इसके बाद यह कार्यशील परमाणु रिएक्टरों के उत्पादन में तेजी ला सकता है जिससे असीमित स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी।

जागरण रिसर्च

Dainik Jagaran Page No-10

जागरण विशेष

दुर्गम व पहाड़ी स्थलों पर सैनिकों का सहयोगी बनेगा 'हनुमंता'

आइआइटी दिल्ली के वनाए उपकरण से जवान के पीठ पर लदे वैग का 80 प्रतिशत तक कम महसूस होगा वजन

नंदकिशोर भारद्वाज • जागरण

सोनीपत: सेना के जवान विषम परिस्थितियों में भारी-भरकम हथियार और सामान से भरे वजनी बैग लेकर घंटों तक रेगिस्तान, बर्फीली पहाड़ियों और दुर्गम जंगलों में गश्त करते हैं। इस दौरान भारी वजन के बैग और हथियारों को उठाने के कारण जवानों के घुटनों और पीठ में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आइआइटी दिल्ली के छात्र गौरव राय ने उच्च तकनीक से 'हनुमंता एक्जो-1' तैयार किया है, जिसके कारण सैनिकों के कंधों पर लदा वजन 80-90 प्रतिशत तक कम महसूस होगा। यानी 60 किलो वजन मात्र 10 किलो का लगेगा।

गौरव राय के अनुसार, 'हनुमंता एक्जो-1' उपकरण को गांधीनगर स्थित भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय और सोनीपत स्थित आइआइटी दिल्ली के एडवांस इमेजिंग सेंटर (एआइसी) के सहयोग से दो वर्षों में विकसित किया गया है। यह गर्दन, पीठ से लेकर जूतों तक पहना जाने वाला उपकरण है, जो डेल्टा स्प्रिंग सिस्टम के आधार पर काम करता है, जो भार को अर्थिंग प्रक्रिया के तहत नीचे पीठ की ओर से जमीन की ओर भेजता है। जैसे ही सैनिक इस उपकरण को पहनकर चलते हैं, यह पीठ पर लदे भार को जूतों के जरिए घटाकर जमीन की ओर भेज देता है। स्प्रिंग से बना यह उपकरण मानव शरीर के मसल्स सिस्टम की तरह कार्य करता है। चलने के दौरान पैरों की मूवमेंट के साथ एडजस्ट होकर यह वजन घटाने में सहायक होता है।

मूल रूप से राजस्थान के कोटा के रहने वाले गौरव बताते हैं कि वर्ष 2023 में सोनीपत स्थित कैंपस में इस पर कार्य शुरू हुआ था, जो अब तैयार हो चुका है। गांधीनगर स्थित भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के जरिये सेना और डीआरडीओ के समक्ष इसकी प्रस्तुति हो चुकी है। सेना ने इसे न केवल उपयोगी बताया, बल्कि एआइ से जोड़ने का सुझाव भी दिया है। गौरव के मुताबिक, एआइ से जोड़कर इसे और उन्नत बनाने पर काम हो रहा है।

« सोनीपत में एआइसी में हनुमंता एक्जो-1 को दिखाते गौरव राय • जागरण

सेना से सेवानिवृत्त पिता की सलाह पर किया काम

गौरव राय बताते हैं कि उनके पिता सतेंद्र राय सेना में अधिकारी थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लंबे समय तक भारी बैग लादकर गश्त करने के कारण उन्हें भी पीठ और घुटनों में दर्द की समस्या रहती है। पिता ने ही उन्हें बताया कि यह बड़ी समस्या है और अन्य जवानों को भी इसका सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 'हनुमंता एक्जो-1' का निर्माण करने का विचार किया। पेटेंट की प्रक्रिया अगले माह 15 जनवरी के बाद शुरू होगी।

आइआइटी, दिल्ली के सोनीपत स्थित कैंपस (एआइसी) में ऐसे स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है, जिनका मानव जीवन से सीधा जुड़ाव हो और जो लोगों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम स्टार्टअप को फंड, गाइडेंस और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। शोधार्थियों के यूनीक आइडिया को एक प्रोडक्ट बनाने तक हम मदद करते हैं।

आलोक पांडेय, सीईओ, एआइसी आइआइटी दिल्ली

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

Dainik Jagaran Page No-8

गोवा मुक्ति दिवस

गोवा स्वतंत्रता संग्राम की अनदेखी

अभिषेक रंजन सिंह

अध्यक्ष, डा. राममनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन, दिल्ली

गोवा को आजाद हुए छह दशक से अधिक समय बीत चुका है, किंतु यह मुक्ति पर्व आज भी मुख्यत: गोवा तक ही सीमित रह गया है। यह दिन पूरे भारत का उत्सव होना चाहिए

आज गोवा मुक्ति दिवस की 64वीं वर्षगांठ है। यह दिन न केवल गोवा, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है। साढ़े चार सौ वर्षों के पुर्तगाली शासन के बाद 19 दिसंबर, 1961 को गोवा, दमन और दीव यूरोपीय उपनिवेशवाद से मुक्त हुए। यह दिन गोवा मुक्ति आंदोलन के महानायक डा. राममनोहर लोहिया के अदम्य साहस और ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करने का भी अवसर है। 18 जून, 1946 जिसे गोवा में 'क्रांति दिवस' के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है-कोई सामान्य तिथि नहीं है। इसी दिन डा. राममनोहर लोहिया ने गोवा में नागरिक अधिकारों का प्रश्न उठाकर औपनिवेशिक शासन को खुली चुनौती दी थी। उस दौर में गोवा में स्थिति इतनी दयनीय थी कि लोगों को विवाह के निमंत्रण-पत्र छापने तक की अनुमति नहीं थी, सार्वजनिक सभा करना भी प्रतिबंधित था।

भारत की आजादी के चौदह वर्ष बाद गोवा स्वतंत्र हुआ। यह प्रश्न आज भी उठता है कि आजाद भारत के भीतर रहते हुए भी गोवावासियों को लगभग डेढ़ दशक तक पुर्तगाली शासन क्यों झेलना पड़ा? तत्कालीन सरकार की विवशताएं क्या थीं? इन प्रश्नों पर बहस होती रही है। किंतु दोषारोपण में उलझने के बजाय यह अधिक प्रासंगिक है कि हम आज गोवा मुक्ति आंदोलन के नायकों को किस रूप में स्मरण कर रहे हैं। गोवा साढ़े चार सौ वर्षों तक पुर्तगाली दासता में रहा। यह कोई छोटा कालखंड नहीं है, किंतु दुर्भाग्यवश गोवा मुक्ति संग्राम और उसके स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास लेखन में वह स्थान नहीं मिला, जिसके वे अधिकारी थे। परिणामस्वरूप आज देश के छात्रों और युवाओं में इस आंदोलन के प्रति पर्याप्त जानकारी का अभाव है। गोवा की आजादी केवल गोवावासियों की नहीं, बल्कि पूरे भारत की आजादी का अभिन्न हिस्सा है। आजादी को न तो छोटा-बड़ा कहा जा सकता है और न ही इसे समय-सीमा के आधार पर आंका जाना चाहिए। आज गोवा की पहचान प्रायः पर्यटन स्थल के रूप में बन गई है, जबकि डा. राममनोहर लोहिया ने 1946 में अपनी पुस्तक 'एक्शन इन गोवा' में इसके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भविष्य की दूरदर्शी कल्पना प्रस्तुत की थी।

गोवा की आजादी में डा. लोहिया के साथ-साथ टीबी कुन्हा, मनोहर राय सरदेसाई और बालकृष्ण भगवंत बोरकर जैसे मराठी और कोंकणी साहित्य के महान रचनाकारों का भी अमूल्य योगदान रहा। 18 जून, 1946 की ऐतिहासिक घटना के बाद गोवा मुक्ति आंदोलन में देश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों लोग शामिल हुए और अनेक ने अपने जीवन का बलिदान दिया। डा. लोहिया ने इस आंदोलन को क्षेत्रीय न रखकर राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया। यही कारण था कि 1954-55 के दौरान त्रिदीब चौधुरी, मधु लिमये, जगन्नाथ राव जोशी और जमुना प्रसाद शास्त्री जैसे नेताओं ने गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और महीनों जेल की यातनाएं सहीं।

19 दिसंबर, 1961 को गोवा की स्वतंत्रता ने विश्व के अनेक देशों को प्रेरणा दी। पुर्तगाली उपनिवेशवाद की समाप्ति ने अंगोला, मोजाम्बिक, गिनी-बिसाऊ, केपवर्डे, साओ टोमे और प्रिंसिपे जैसे अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों को नई दिशा दी, जिन्हें 1970 के दशक के मध्य में आजादी मिली। गोवा की मुक्ति ने यह सिद्ध किया कि लंबे समय से चले आ रहे औपनिवेशिक शासन को समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एशिया और अफ्रीका में घाना (1957), मलेशिया (1957), तंजानिया (1961), अल्जीरिया (1962), सिंगापुर (1965), जांबिया (1964) और मालदीव (1965) जैसे देशों के राष्ट्रवादी आंदोलनों को भी इससे प्रेरणा मिली। घाना जैसे नवस्वतंत्र देशों के नेताओं ने गोवा की आजादी को उपनिवेशवाद के खिलाफ एक निर्णायक झटका माना। पुर्तगाली भारत के पतन ने वैश्विक 'डी-कोलोनाइजेशन' की प्रक्रिया को गति दी और यह स्पष्ट कर दिया कि यूरोपीय साम्राज्यों का अंत निकट है।

गोवा को आजाद हुए छह दशक से अधिक समय बीत चुका है, किंतु यह मुक्ति पर्व आज भी मुख्यतः गोवा तक ही सीमित रह गया है। यह दिन पूरे भारत का उत्सव होना चाहिए। माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों में गोवा मुक्ति संग्राम और उसके महानायकों का समुचित उल्लेख होना आवश्यक है। सरकार को इस दिशा में गंभीर पहल करनी चाहिए। गोवा मुक्ति आंदोलन कोई साधारण घटना नहीं थी। साढ़े चार सौ वर्षों की दासता ने गोवा की सभ्यता और संस्कृति को गहरी चोट पहुंचाई। इसलिए देश की युवा पीढ़ी को इस गौरवशाली संघर्ष से परिचित कराना समय की आवश्यकता है।

भारत की आजादी के आंदोलन की तरह इतिहास में प्रमुखता से शामिल हो गोवा मुक्ति संग्राम। फाइल

Dainik Jagaran Page No-9

राष्ट्रीय संस्करण www.jagran.com

दैनिक जागरण

शुक्रवार 19 दिसंबर, 2025

1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे सरकार के तीसरे स्तर के रूप में जाना जाता है।

विम

आजकल

समावेशी विकास की ओर कदम

डा. सुशील कुमार सिंह

निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन आफ पालिसी एवं एडमिनिस्ट्रेशन, देहरादून

विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी जी-राम-जी विधेयक ग्रामीण रोजगार नीति को एक नए सोच के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है। यह मनरेगा की मूल भावना से प्रेरणा लेते हुए रोजगार को अवसंरचना निर्माण, आजीविका सृजन और दीर्घकालिक विकास से जोड़ता है। यदि इसे संवेदनशीलता, पारदर्शिता और केंद्र-राज्य सहयोग की भावना के साथ लागू किया जाता है, तो यह ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है

करीब एक अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत रोजगार और आजीविका के मामले में संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। जब बात ग्रामीण परिवेश की होती है तो यही संघर्ष कई गुना बढ़ा हुआ नजर आता है। 20 वर्षों से चल रही मनरेगा योजना के स्थान पर केंद्र सरकार नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बना रही है, जिसका नाम है विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी जी-राम-जी बिल। इसमें विकसित भारत-2047 का राष्ट्रीय विजन निहित है। जब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत हुआ तो भारत के समक्ष दो मूल मुद्दे थे-राष्ट्र निर्माण और सामाजिक-आर्थिक प्रगति। इसी पृष्ठभूमि में विकास प्रशासन की अवधारणा सामने आई और समाज के बहुमुखी तथा नियोजित विकास पर बल दिया जाने लगा। आवाजविहीन, जड़विहीन और भविष्यविहीन विकास को तभी रोका जा सकता है, जब इसके लिए सुनियोजित और दूरदर्शी कदम निरंतर उठाए जाएं। इसी क्रम में समावेशी विकास की परिकल्पना सामने आती है, जिसमें रोजगार के अवसर निहित होते हैं और गरीबी उन्मूलन को एक केंद्रीय लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। अवसर की समानता, शिक्षा और कौशल के माध्यम से लोगों को सशक्त करना भी इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। बुनियादी सुविधाएं-जैसे आवास, भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य उपलब्ध कराना तथा आजीविका के साधनों को निरंतर सुदृढ़ बनाना समावेशी विकास की लक्ष्याभिमुख अवधारणा को स्पष्ट करता है।

उल्लेखनीय है कि देश अनेक ढांचों और उनमें निहित विकास की परतों से युक्त है, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी आयाम शामिल हैं। इसी क्रम में 21वीं सदी के पहले दशक के मध्य में समावेशी विकास को मजबूती देने के उद्देश्य से फरवरी 2006 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में इसे नरेगा अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा गया और दो अक्टूबर, 2009 से महात्मा गांधी का नाम जोड़ते हुए इसे मनरेगा का स्वरूप दिया गया। इसका मूल उद्देश्य देश के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना था। इस योजना से अब तक करोड़ों नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से एक क्रांतिकारी पहल रही है। इसने समावेशी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ पलायन, गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुशासन की कसौटी पर देखें तो मनरेगा लोक सशक्तीकरण के साथ कदमताल करती हुई आजीविका आधारित बुनियादी विकास की एक प्रभावी व्यवस्था के रूप में सामने आती है।

इसके स्थान पर आ रही जी-राम-जी बिल एक ऐसी ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दिए जाने का प्रविधान है। ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण, मौसम की मार को कम करने के लिए विशेष कार्य, आजीविका से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर और जल से जुड़े कार्य इस नए बिल के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसे पीएम गति शक्ति प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, आय में वृद्धि होगी और सड़क निर्माण, कनेक्टिविटी तथा बाजार तक पहुंच बेहतर होगी। गांवों में कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी और भंडारण, बाजार एवं उत्पाद के माध्यम से आजीविका के अवसर विस्तारित होंगे। जी-राम-जी बिल के विभिन्न पहलुओं पर यदि गहराई से विचार किया जाए तो इसमें रोजगार, पारदर्शिता, आजीविका, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अनेक तत्व शामिल हैं, जो ग्रामीण जीवन की दिशा और दशा को बेहतर बना सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का है और इसे हासिल करने के लिए योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन या नई योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक होगा। हालांकि भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की चुनौतियां देश में हमेशा से रही हैं। यदि जवाबदेही सुदृढ़ नहीं हुई तो योजना चाहे जितनी भी महत्वाकांक्षी क्यों न हो, अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगी।

आर्थिक सुधारों के संदर्भ में 24 जुलाई, 1991 का उदारीकरण एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसके बाद 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्थानीय स्वशासन, जिसे सरकार के तीसरे स्तर के रूप में जाना जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक मजबूत आधार बना। पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि लोकतांत्रिक ढांचा किस प्रकार सशक्त हुआ है। इन्हीं संस्थाओं को मनरेगा के अंतर्गत कार्यों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था और मनरेगा ने मिलकर समावेशी विकास की अवधारणा को मजबूती प्रदान की है। मनरेगा की तरह जी-राम-जी भी मूलतः अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल निर्माण को पर्याप्त बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक स्थायी रोजगार की संभावनाएं सीमित ही रहेंगी।

भारत गांवों का देश है, जहां कई पंचायतें और गांव अब भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटरनेट जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में जी-राम-जी योजना एक सशक्त माध्यम बन सकती है। हालांकि मनरेगा भी भ्रष्टाचार और सोशल आडिट जैसी चुनौतियों से जूझती रही है। यही सावधानी जी-राम-जी के संदर्भ में भी आवश्यक होगी कि निगरानी, पारदर्शिता और मूल्यांकन प्रभावी हों, ताकि योजना कागज से निकलकर जमीन पर उतर सके। यह स्पष्ट है कि गांव मजबूत होंगे, तभी देश मजबूत होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार, आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और समावेशन को प्राथमिकता दिए बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। योजनाओं का सही और ईमानदार क्रियान्वयन ही सफलता की कुंजी है। यदि जी-राम-जी योजना इस कसौटी पर खरी उतरती है, तो निस्संदेह यह ग्रामीण आजीविका और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

ग्रामीण भारत को सशक्त बनाए बिना संभव नहीं विकसित भारत का निर्माण। फाइल

मनरेगा से आगे : ग्रामीण रोजगार की नई दिशा

देवेंद्रराज सुथार

विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक ग्रामीण भारत के विकास को नए दृष्टिकोण से देखने का संकेत देता है। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को सामने रखकर यह विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केवल मजदूरी आधारित राहत से आगे ले जाकर स्थायी आजीविका और मजबूत अवसंरचना से जोड़ने की मंशा को दर्शाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू गारंटीकृत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करना है। यह कदम सीधे तौर पर ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को मजबूत करता है। बढ़े हुए रोजगार दिवस का अर्थ है अधिक काम के अवसर, अधिक मजदूरी और स्थानीय अर्थव्यवस्था में अधिक नकदी का प्रवाह। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मौसमी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, वहां अतिरिक्त रोजगार दिवस ग्रामीण जीवन में स्थिरता लाने में सहायक हो सकते हैं। यदि इस प्रविधान को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो यह ग्रामीण गरीबी घटाने और पलायन रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मजदूरी भुगतान का बोझ केंद्र और राज्यों के बीच साझा करने का प्रस्ताव संघीय ढांचे की भावना को मजबूत करता है। इससे राज्य सरकारों की भागीदारी और जवाबदेही बढ़ सकती है। उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का अनुपात यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय असमानताओं और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लचीला दृष्टिकोण अपना रही है। अन्य राज्यों के लिए 60:40 का अनुपात राज्यों को योजना के साथ अधिक गहराई से जुड़ने का अवसर देता है। इस साझा जिम्मेदारी से राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कामों की योजना बनाने और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा मिल सकती है।

नए विधेयक में श्रम बजट की मांग-आधारित व्यवस्था के स्थान पर ''मानक आवंटन'' प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव भी बेहतर नियोजन की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। वार्षिक आवंटन पहले से तय होने से राज्यों को योजना बनाने में स्पष्टता मिलेगी और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा। इससे परियोजनाओं में अनुशासन आ सकता है और कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिल सकती है। कृषि मौसम के दौरान 60 दिनों के लिए रोजगार योजना को स्थगित करने का प्रविधान कृषि और ग्रामीण रोजगार नीति के बीच संतुलन स्थापित करने के सोच को दर्शाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बोआई और कटाई जैसे महत्वपूर्ण समय में किसानों को पर्याप्त श्रमिक मिल सकें।

ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड की शुरुआत भी इस विधेयक का एक सराहनीय पहलू है। तीन वर्ष की वैधता वाले इन कार्डों से लाभार्थियों की पहचान और रिकार्ड प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकता है। एकल महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, मुक्त बंधुआ मजदूरों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग रंग के कार्ड जारी करने का प्रस्ताव सामाजिक समावेशन की भावना को मजबूत करता है। इससे इन वर्गों तक योजना का लाभ पहुंचाने में सहूलियत हो सकती है और उनकी विशेष जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है।

(शोधार्थी)

Dainik Jagaran Page No-9

अफगानिस्तान में चिकित्सा सेवाओं का आधारभूत ढांचा खड़ा करने में मदद करेगा भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अफगानिस्तान में चिकित्सा सेवाओं के आधारभूत ढांचे के विकास के साथ ही गंभीर चिकित्सा सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने में भारत मदद करेगा। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली के साथ मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरसंभव मदद का भरोसा दिया। इससे आने वाले वर्षों में इलाज के लिए अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। गुरुवार को दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों की बातचीत में अफगानिस्तान में अहम मेडिकल प्रोजेक्ट को लागू करने का फैसला लिया गया। इनमें पटकिया, खोस्त और पाकटिका प्रांत में पांच मातृत्व व स्वास्थ्य क्लिनिक खोलने के साथ काबुल में 30 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण शामिल है। इसके अलावा काबुल में कैंसर उपचार सेंटर, ट्रामा सेंटर, डायगनैस्टिक सेंटर और थैलेसीमिया सेंटर खोलने का भी निर्णय हुआ। अफगानिस्तान की ओर से की गई अन्य मांगों पर विचार का भरोसा दिया गया।

- नए अस्पताल से खोलने से लेकर दवाओं और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति का समझौता

नई दिल्ली में गुरुवार को अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। प्रेट

जेपी नड्डा ने कहा कि मानवीय सहायता के तहत भारत अफगानिस्तान को पिछले चार वर्षों में 327 टन दवाएं भेज चुका है। अफगानिस्तान के अनुरोध पर कैंसर दवाओं और सीटी स्कैन मशीन को भेजने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा रेडियेरी मशीन और अतिरिक्त दवाएं भेजने की प्रक्रिया जारी है। भारत में अफगानिस्तान के लोगों का गंभीर बीमारियों से मुफ्त इलाज की सुविधा जारी रहेगी। इसके तहत अप्रैल से अब तक 200 मेडिकल वीजा जारी किया जा चुका है।

शेयर बाजार संहिता में होगा बदलाव, सिक्युरिटी मार्केट्स कोड बिल पेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार और बाजार में निवेशकों व निवेश में भारी वृद्धि को देखते हुए सरकार शेयर बाजार संबंधी संहिता को सरल और पारदर्शी बनाने जा रही है। इसके तहत गुरुवार को संसद में सिक्युरिटी मार्केट्स कोड (एसएमसी) बिल, 2025 पेश किया गया। हालांकि इस बिल को वित्त से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। इसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के सदस्यों की संख्या नौ से 15 करने का प्रस्ताव रखा गया है।

इस बिल का उद्देश्य शेयर बाजार, म्युचुअल फंड, बांड आदि से जुड़ी अलग-अलग संहिताओं को एक बनाना है ताकि यह निवेशकों की रक्षा के साथ पूंजी को इकट्ठा कर सके। अलग-अलग संहिता होने से कई संहिताएं एक जैसी थीं, जिन्हें समाप्त कर दिया गया है। भाषा सरल की गई है ताकि निवेशक उसे आसानी से समझ सकें। अनुपालन नियम कम किया गया है, टेक्नोलाजी को अपनाने पर जोर दिया गया है जिससे कारोबार व निवेश आसान हो सके।

डच विदेश मंत्री से मिले राजनाथ, रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली, प्रेट : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां डच विदेश मंत्री डेविड वान वील से भेंट की, जिसमें दोनों नेताओं ने "सह-विकास और सह-उत्पादन" के लिए रक्षा उपकरणों के प्राथमिक क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। भारत-नीदरलैंड के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता पत्र भी दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह व भारत में नीदरलैंड के राजदूत मारिस गेराड्स ने गुरुवार को इन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया।

- भारत-नीदरलैंड के मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी की पुष्टि की
- रक्षा सचिव राजेश और नीदरलैंड के राजदूत ने किया दस्तावेजों का आदान-प्रदान

नई दिल्ली में गुरुवार को नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वान वील को स्मृति चिह्न भेंट करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट

रक्षा मंत्रालय ने कहा,राजनाथ सिंह ने डच विदेश मंत्री के साथ भेंट में "दोनों देशों के बीच मजबूत और बढ़ती रक्षा साझेदारी" की पुष्टि की। दोनों ने द्विपक्षीय सुरक्षा व रक्षा मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें रक्षा उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन के प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने सैन्य सहयोग को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। चर्चाओं में भारत-नीदरलैंड के बीच स्वतंत्र, खुला, समावेशी व नियम-आधारित हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता की भी उजागर किया गया। तकनीक के क्षेत्र में दोनों नेताओं ने "नजदीकी रक्षा साझेदारी" की जरूरत और दोनों देशों की रक्षा उद्योगों को जोड़ने पर जोर दिया। दोनों देशरक्षा सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने का इरादा रखते हैं, ताकि प्रौद्योगिकी सहयोग, सह-उत्पादन और प्लेटफार्मों और उपकरणों के सह-विकास के लिए एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप विकसित किया जा सके। सिंह के हवाले से बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच जनसंपर्क संबंध बहुत मजबूत हैं, जिसमें नीदरलैंड में एक बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय एक जीवित पुल के रूप में कार्य कर रहा है और मित्रता के बंधनों को मजबूत कर रहा है।

Dainik Jagaran Page No-3

रूपरेखा तैयार

आपदा प्रबंधन में माडल बनेंगे 20 राज्यों के 20 गांव

प्राकृतिक आपदा से निपटने की गृह मंत्री शाह के आह्वान को धरातल पर उतारेगा पंचायतीराज मंत्रालय, देशभर के 81 संवेदनशील जिलों से चिन्हित किए जाने हैं गांव, दो वर्ष की कार्ययोजना पर खर्च होंगे 507.37 करोड़ रुपये

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भौगोलिक परिस्थितियों के कारण देश के अलग-अलग राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। इनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) सक्रिय रहते हैं, पर गृह मंत्री अमित शाह ने बिजन दिया कि जो गांव बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, तट क्षरण व नदियों के कटाव जैसी छह प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। यदि उसी पहले मोर्चे पर तैयारी मजबूत की जाए तो बेहतर होगा।

गृह मंत्री के इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय और एनडीएमए ने विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत ऐसी परिस्थितियों से जूझने वाले 20 राज्यों में एक-एक गांव को आपदा प्रबंधन के माडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।

गृह और पंचायतीराज मंत्रालय ने इस दो वर्षीय कार्यक्रम को इस उद्देश्य के साथ तैयार किया है कि आपदा के बाद इससे निपटने के स्थान पर आपदा से पहले ही बचाव व जोखिमों को कम से कम करने की तैयारी गांव स्तर पर कर ली जाए। इसके तहत 20 राज्यों में प्राकृतिक आपदा के मामले में संवेदनशील 81 जिलों को कार्ययोजना में शामिल किया गया है। इसके दायरे में कुल 1620 ग्राम पंचायतें आ रही हैं।

केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य स्वयं चिन्हित करें कि उनके क्षेत्र में जिस आपदा की आशंका सबसे अधिक रहती है, उसकी तैयारी के लिए एक गांव को माडल के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित करें। इसके बाद चिन्हित गांव की ग्राम पंचायत विकास योजना में संबंधित आपदा के प्रबंधन का एकीकरण किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण की योजना है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे सरपंच व अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण, पंचायत कार्यकर्ताओं के लिए कौशल विकास, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों के साथ सीधा जुड़ाव, सामुदायिक स्वयंसेवकों (आपदा मित्रों) तैयार करना, एनसीसी, एनएसएस के माध्यम से युवा संगठन तैयार करना, बहुस्तरीय शमन रणनीति आदि को शामिल किया जाएगा। यह दो वर्ष का कार्यक्रम वर्ष 2027 तक चलेगा, जिसमें बीस माडल गांव देशभर में तैयार हो जाएंगे। वह जिस कुशलता से आपदा से निपटेंगे, उसका अनुकरण देश के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए गत दिवस उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह कुल 507.37 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति दे चुके हैं।

****

राज्य	चिन्हित जिले	आपदा प्रबंधन
उत्तर प्रदेश	छह	भूकंप या बाढ़
केरल	छह	तटीय क्षरण
ओडिशा	छह	चक्रवात या सूखा
असम	छह	बाढ़
महाराष्ट्र	छह	सूखा या भूकंप
राजस्थान	छह	सूखा या बाढ़
तमिलनाडु	पांच	चक्रवात या सूखा
बिहार	पांच	भूकंप या बाढ़
गुजरात	पांच	भूकंप या बाढ़
हिमाचल प्रदेश	तीन	बाढ़ या भूस्खलन
उत्तराखंड	तीन	बाढ़ या भूस्खलन
अरुणाचल प्रदेश	तीन	बाढ़ या भूस्खलन
सिक्किम	तीन	भूस्खलन
मेघालय	तीन	बाढ़ या भूस्खलन
कर्नाटक	तीन	सूखा या भूस्खलन
आंध्र प्रदेश	तीन	चक्रवात या भूस्खलन
पंजाब	दो	भूकंप या नदी का कटाव
नगालैंड	दो	भूस्खलन
मिजोरम	दो	बाढ़ या भूस्खलन

Dainik Jagaran Page No-3

गांधी मैदान में आज से 28 दिसंबर तक होगा आयोजन, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे उद्घाटन

ग्रामीण भारत महोत्सव में देशभर के शिल्पकार जुटेंगे

पटना, हिन्दुस्तान टीम। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव-बिहार 2025 का दूसरा चरण शुक्रवार से 28 दिसंबर तक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस इस भव्य प्रदर्शनी-सह-बिक्री मेले में देशभर के कारीगरों, शिल्पकारों, स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक संगठनों और उद्यमियों के हस्तनिर्मित, जैविक व पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, उद्यमी और शैक्षणिक जगत के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण उत्पादकों को प्रत्यक्ष बाजार उपलब्ध कराना, ब्रांड की पहचान बनाना और उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना है। यह मंच उत्पादों के लिए थोक व दोहराव वाली मांग, उपभोक्ता प्रतिक्रिया, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता तथा उद्यमिता कौशल विकास के अवसर भी प्रदान करता है। साथ ही, विकास एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में यह महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- ग्रामीण कृषि स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्यमियों की सहभागिता भी रहेगी

रोज सुबह 10 से शुरू होगी प्रदर्शनी

यह प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी। प्रवेश निःशुल्क है। आयोजन स्थल गांधी मैदान (गेट नंबर 10 के पास) रहेगा। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से इस महोत्सव में पहुंचकर ग्रामीण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उद्यमिता का अनुभव करने की अपील की है।

ग्रामीण भारत महोत्सव-बिहार 2025 में बिहार सहित देश के 16 राज्यों के विशिष्ट उत्पादों की आकर्षक शृंखला प्रदर्शित की जाएगी। इनमें हिमाचल प्रदेश का शाल, केरल की नेटीपट्टम कला, बनारसी साड़ी, भागलपुर का तसर रेशम, मधुबनी चित्रकला, पटना की कलमकारी, लखनऊ की चिकनकारी, कश्मीर का पश्मीना, मिथिला मखाना, जोधपुर के बंधेज वस्त्र, असम सिल्क, जयपुरी रजाई, ब्लू पॉटरी, टीकमगढ़ के पीतल के बर्तन, मिट्टी और बांस से बने उत्पाद सहित अनेक भौगोलिक संकेत (जीआई) प्राप्त ग्रामीण उत्पाद शामिल हैं। ये उत्पाद दर्शाते हैं कि ग्रामीण भारत के उत्पाद अब बड़े बाजारों में आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं।

महोत्सव में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना, ग्रामीण कृषि स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्यमियों की सहभागिता भी रहेगी। आगंतुकों को प्रतिस्पर्धी कीमत पर गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण उत्पाद खरीदने का अवसर मिलेगा, साथ ही बिहार के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी चख सकेंगे।

कार्यालय नगर पालिका हिण्डोली जिला - बून्दी (राज0)

Hindustan Page No-7

बांग्लादेश में चीन के बढ़ते दखल पर संसदीय समिति ने गंभीर चिंता जताई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की गई

समिति ने रिपोर्ट में बांग्लादेश की स्थिति को भारत के लिए चुनौती बताया गया

विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक स्थिति भारत के लिए 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद सबसे गंभीर रणनीतिक चुनौती बन गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली इस समिति की रिपोर्ट गुरुवार को संसद में पेश की गई। रिपोर्ट में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथी ताकतों की वापसी और चीन-पाक के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा किया गया है। खास तौर पर चीन की तरफ से बांग्लादेश में एयरबेस, पनडुब्बियों के लिए बेस बनाने व जमात-ए-इस्लामी को लुभाने की कोशिशों का मुद्दा समिति ने उठाया है और सरकार को वहां सक्रिय विदेशी शक्तियों की गतिविधियों पर करीबी नजर रखने का सुझाव दिया है।

इस रिपोर्ट को काफी सामयिक कहा जा सकता है। बांग्लादेश में अभी जबरदस्त राजनीतिक अस्थिरता है। वहां के अतिवादी छात्र समूह निरंतर भारत की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। समिति ने कहा, हांलाकि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति वर्ष 1971 की स्थिति से अलग है,पर वहां की राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी ताकतों का मिश्रण अधिक जटिल, दीर्घकालिक व संरचनात्मक चुनौती पैदा करने की क्षमता रखते हैं। यह क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की पड़ोस नीति को प्रभावित कर सकता है।

पूर्व पीएम शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में जिस तरह से चीन की सक्रियता बढ़ी है, उसे विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। समिति ने मोंगला बंदरगाह के विस्तार का जिक्र किया है, जहां चीन ने मो. यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ करीब 40 करोड़ डालर की परियोजना लागू करने के लिए समझौता किया है। यह बंदरगाह कोलकाता के करीब है और इस परियोजना को चीन की 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' चीन की भू-राजनीतिक रणनीति है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बंदरगाहों व सैन्य ठिकानों का नेटवर्क बनाना शामिल है, ताकि वह अपने समुद्री प्रभाव को बढ़ा सके और भारत को घेर सके। समिति ने लालमोनिरहाट एयरबेस के विकास में चीन की मदद पर भी गंभीर चिंता जताई है। यह एयरबेस भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर दूर है और सिलिगुड़ी कारिडोर (चिकन नेक) से करीब है। वैसे बांग्लादेशी सेना ने कहा है कि फिलहाल इसका सैन्य उपयोग नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट इसे सुरक्षा के लिए खतरा मानती है।

समिति ने जमात-ए-इस्लामी नेताओं की हालिया चीन यात्रा का भी उल्लेख किया, जो बांग्लादेश में विभिन्न गुटों के साथ उसके व्यापक जुड़ाव का संकेत देती है। इसके अलावा, पेकुआ में चीन द्वारा निर्मित पनडुब्बी बेस का जिक्र किया गया है। इस बेस पर आठ पनडुब्बियों को समायोजित करने की क्षमता तैयार की जा रही है, जबकि बांग्लादेश के पास केवल दो पनडुब्बियां हैं। यह बंगाल की खाड़ी में चीन की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की नीति की तरफ संकेत देता है।

रिपोर्ट में भारत की 'शांत कूटनीति' की सराहना की गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से समिति को बताया गया है कि चीन की उपस्थिति लंबे समय से है यह और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों का परिणाम नहीं है। भारत ने खुलना-मोंगला रेलवे लिंक के लिए वित्तीय सहायता की है और पारगमन सुविधाओं के लिए समझौते किए हैं। समिति ने सिफारिश की कि सरकार बांग्लादेश में विदेशी शक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखे। विशेष रूप से सैन्य आधार स्थापित करने की कोशिशों की निगरानी जरूरी है, जो भारत के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं। साथ ही विकास सहयोग में भारत के तुलनात्मक लाभ का उपयोग कर विश्वास बढ़ाने और अपनी स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया गया।

शेख हसीना को शरण देने का समर्थन : प्रेटू के अनुसार, संसदीय समिति ने कहा है कि उसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत द्वारा शरण देने पर ध्यान दिया है। इस संबंध में देश का दृष्टिकोण उसकी सभ्यतागत नैतिकता और मानवीय परंपरा से प्रेरित है, जिसके तहत गंभीर संकट या अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे व्यक्तियों को शरण दी जाती है। समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को भारत के मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरूप अपना सैद्धांतिक और मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए।

Dainik Jagaran Page No-3

नहीं रहे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू आफ यूनिटी बनाने वाले राम सुतार

जागरण संवाददाता, नोएडा : मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की भव्य प्रतिमा व बच्चों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने की अधूरी इच्छा दिल में संजोए प्रसिद्ध मूर्तिकार राम जी सुतार नहीं रहे। गुरुवार को 100 वर्ष, 10 महीने की आयु में नोएडा स्थित आवास पर अंतिम सांस ली।

सुतार ने जीवनकाल में एक हजार से अधिक मूर्तियों को आकार दिया। देश-विदेश के अनेक शहरों में स्थापित उनकी कृतियां भारतीय संस्कृति, शौर्य व मूल्यों की पहचान हैं। उनकी बनाई गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची 'स्टैच्यू आफ यूनिटी' विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। वे पद्मश्री, पद्मभूषण समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके थे। 2021 में ग्रेटर नोएडा में दैनिक जागरण की ओर से आयोजित जागरण विमर्श कार्यक्रम में उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया था।

राम वी सुतार की फाइल फोटो। जागरण

एक साल पहले दैनिक जागरण से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि उनकी दो इच्छा अब भी शेष हैं। वह यह कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दो बच्चों के साथ वाली मूर्ति सबसे ऊंचे आकार में बनाएं। प्रभु श्रीराम की सरयू पर जो मूर्ति बनानी है, उसे भी ईश्वर उन्हें बनाने का अवसर दें। उनके बेटे अनिल सुतार ने बताया कि श्रीराम की प्रतिमा और बच्चों के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा समुद्र के बीच बनाने की थी। यह इच्छा पूरी न होने पर उन्होंने पटना में 40 फीट की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई।

विच्छू की आकृति से शुरू हुआ था सफर : मूलरूप से महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंदूर के सुतार मूर्तिकार बनने का जुनून लेकर दिल्ली आए। पहली आकृति पांच वर्ष की उम्र में पेन से पेपर पर बिच्छू की उकेरी थी।

राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया शोक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी एक्स पर मराठी भाषा में संवेदना व्यक्त की। लिखा-राम सुतारजी के निधन से दुख हुआ। वे एक शानदार मूर्तिकार थे। उनके काम को हमेशा देश के इतिहास, संस्कृति व सामूहिक भावना की दमदार अभिव्यक्ति के तौर पर सराहा जाएगा।

Dainik Jagaran Page No-2

संकट : देश के छोटे शहरों में भी सेहत बिगाड़ रही जहरीली हवा

दिल्ली में हर सांस के साथ लोग जहरीली हवा को अंदर ले रहे हैं और इसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। प्रदूषण से अस्पतालों में मरीजों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के शहरों में भी वायु गुणवत्ता खराब होने से लोग बीमार हो रहे हैं। जहरीली हवा सेहत के लिए गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरी है। पेश है आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' की विशेष सीरीज की दूसरी कड़ी-

बिहार

बाल झड़ने की समस्या से लेकर त्वचा भी खराब कर रहा प्रदूषण

पटना। बिहार में वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पटना की हवा में फैले धूलकण से सबसे अधिक सांस की बीमारी वाले मरीज परेशान हो रहे हैं। अस्पतालों में सांस से जुड़ी परेशानी, बाल झड़ने-टूटने और त्वचा की बीमारी के 30 फीसदी मरीज बढ़ गए हैं।

आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच समेत दूसरे अस्पतालों में सांस से संबंधित बीमारी (सीओपीडी) के मरीज बढ़े हैं। आईजीआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने बताया कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों के बाल तेजी से झड़ रहे हैं। आंखों में पीलापन के केस में भी इजाफा हुआ है। डॉ.पीके अग्रवाल ने बताया कि पहले से जिनको दमा, अस्थमा और सांस फूलने की शिकायत रही है, उनकी परेशानी दोगुनी बढ़ गई है। हृदय पर भी इसका असर पड़ता है। हॉर्ट अटैक की संभावना बनी रहती है।

30 फीसदी मरीजों की संख्या बढ़ गई अस्पतालों में

जाम से हवा खराब

- यातायात जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतार
- पुराने और जर्जर वाहनों से निकलने वाला धुआं
- सड़कों पर जमा धूल उड़ना, बालू लदे ट्रकों की आवाजाही
- खुले में कचरा जलाना, निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी

जमीनी हकीकत: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को राज्य में प्रदूषण की निगरानी का विशेष जिम्मा है। पर्षद की ओर से मानकों के उल्लंघन की निगरानी को विशेष टीम बनी है।

जब एक्यूआई का स्तर 400 से अधिक हो जाता है, तो स्वस्थ लोगों को भी गले में जलन, थकान, ऊपरी श्वसन संक्रमण और आंखों की समस्या हो सकती है। जिन लोगों का दिल कमजोर है, उनके लिए प्रदूषण दिल की विफलता का कारण बन सकता है।

नई दिल्ली में गुरुवार को हवा का स्तर खराब होने इंडिया गेट में छाई धुंध।

कब कितने मरीज पहुंचे

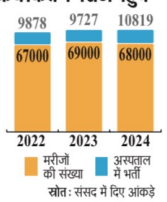

स्रोत: संसद में दिए आंकड़े

किसका कितना हिस्सा

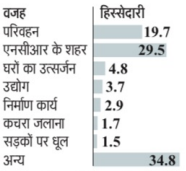

स्रोत: पृथ्वी मंत्रालय, डीएसएस डाटा

उम्रवार असर: बच्चे अत्यधिक खतरे में

बच्चे (शून्य से 18 वर्ष)

लैंसेट और डब्ल्यूएचओ के अध्ययन के अनुसार प्रदूषण से बच्चे सबसे अधिक खतरे में होते हैं।

क्या असर?

- **बचपन का अस्थमा:** बच्चों में फेफड़ों की कार्यक्षमता और आकार में असर पड़ सकता है।
- **संज्ञानात्मक विकास :** मानसिक विकास और सीखने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है।

युवा और वयस्क (19 से 60)

इस आयु वर्ग का बड़ा हिस्सा काम के सिलसिले में बाहर रहता है, इसलिए वे बाहरी प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं।

क्या असर?

- **हृदय रोग:** हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
- **प्रजनन क्षमता :** हार्मोनल संतुलन बिगड़ रहा है।
- **क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस :** लगातार खांसी और सांस फूलने की समस्या

बुजुर्ग (60 वर्ष से ऊपर)

उम्र के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे पहले से मौजूद बीमारियों को घातक बना देता है।

क्या असर?

- **सीओपीडी और सांस रुकना:** फेफड़ों की पुरानी बीमारियां बढ़ जाती है
- **डिमेंशिया:** अल्जाइमर का खतरा बढ़ता है।
- **कैंसर:** फेफड़ों के कैंसर की संभावना ज्यादा।

दिल्ली में सांसों की बीमारियों को बढ़ा रहा प्रदूषण

नई दिल्ली। दिल्ली का वायु प्रदूषण संकट अब सिर्फ एक पर्यावरणीय चिंता नहीं रह गया है। यह अब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी बन गई है। रोजाना अस्पतालों के वार्डों और ओपीडी में देखने को मिल रही है। संसद में पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में 2022 और 2024 के बीच सांस की गंभीर बीमारियों के 2 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया गया।

Hindustan Page No-21

बिहार सभासार अपनाने में देश में पांचवें स्थान पर

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार की ग्राम पंचायतें तकनीक के सहारे पारदर्शिता और आधुनिक प्रशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों में सभासार (एआई आधारित एप्लिकेशन) को अपनाने वाले राज्यों में बिहार देश में पांचवें स्थान पर है।

राज्य की 5053 ग्राम पंचायतें पहले ही इस एप से ग्राम सभा और पंचायत बैठकों का डिजिटल दस्तावेजीकरण कर रही है। पंचायती राज मंत्रालय ने 14 अगस्त 2025 को सभासार की शुरुआत की थी। यह एक एआई आधारित एप्लिकेशन है, जो ग्राम सभा की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को स्वतः लिखित रूप में बदल देता है। सभासार 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे स्थानीय भाषा में काम करना पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आसान हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की 74.36% ग्राम पंचायतें सभासार का प्रयोग कर रही हैं। यह आंकड़ा बताता है कि नीति निर्माण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एआई तकनीक के उपयोग को लेकर बिहार की पंचायतें देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुकी हैं।

- **बिहार में 74 प्रतिशत पंचायतों में एप का उपयोग**
- **ग्राम पंचायतों में बैठकों का डिजिटल दस्तावेजीकरण हो रहा**

पंचायतों की जवाबदेही में सुधार आया

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और बिहार के पंचायती राज विभाग पंचायतों को लगातार सभासार अपनाने और उसके प्रभावी उपयोग के लिए जागरूक कर रहा है। पंचायतों की जवाबदेही और कार्यकुशलता दोनों में सुधार आया है। सभासार अपनाने वाले देश के शीर्ष पांच राज्यों (प्रतिशत) में तमिलनाडु में 95.12%, ओडिशा में 91.83 प्रतिशत, त्रिपुरा में 88.86%, छत्तीसगढ़ में 74.50% और बिहार में 74.36 प्रतिशत ग्राम पंचायतें इसका प्रयोग कर रही हैं।

Hindustan Page No-10

सुनहरा मौका | कुछ वर्षों पहले तक बिहार के खिलाड़ियों की गिनी-चुनी मौजूदगी ही आईपीएल में होती थी, आकाशदीप गेंदबाजी तो ईशान और वैभव बल्लेबाजी से लोगों का दिल जीतेंगे

आईपीएल में बिहार के आठ क्रिकेटर दिखाएंगे अपना जौहर

पटना, मुख्य संवाददाता। एक समय था जब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में बिहार के खिलाड़ियों की मौजूदगी गिनी-चुनी होती थी, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। वर्ष 2026 के आईपीएल में बिहार के आठ खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरते नजर आएंगे। यह न सिर्फ राज्य के क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व का क्षण है बल्कि बिहार क्रिकेट के बदलते परिदृश्य की भी मजबूत तस्वीर पेश करता है। इस बार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) से खेलने वाले सुपौल जिले के इजहार और गोपालगंज के शाकिब हुसैन का चयन आईपीएल के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में निरंतर अच्छे प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। इजहार अपनी सधी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, वहीं शकीबुल गनी बल्लेबाजी के साथ-साथ ऑलराउंड प्रदर्शन की क्षमता रखते हैं। आईपीएल 2026 में कोई खिलाड़ी गेंदबाजी से तो कोई बल्लेबाजी से अपनी पहचान बनाएगा। राज्य के क्रिकेट इतिहास में यह सीजन एक नए अध्याय के रूप में याद किया जाएगा इसके अलावा केकेआर से आकाशदीप, एसआरएच से ईशान किशन, डीसी से मुकेश कुमार, केकेआर से सार्थक रंजन, एसआरएच अमित और राजस्थान रॉयल्स से वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी भी आईपीएल 2026 में नजर आएंगे, जिनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी दूसरे राज्यों की ओर से खेलते हैं। रोहतास के आकाशदीप अपनी तेज गेंदबाजी से पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं। पटना निवासी ईशान किशन आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और आईपीएल के बड़े मंच पर कई यादगार पारियां खेल चुके हैं। वहीं रोहतास के हमीरपुर के अमित और युवा प्रतिभा व समस्तीपुर जिले के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को बिहार क्रिकेट का उभरता सितारा माना जा रहा है जिनसे इस सीजन खास उम्मीदें हैं। अमित स्पिन गेंदबाजी के लिये जाने जाते हैं। वैभव हाल ही में छक्कों का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। वे अंडर 19 भारतीय टीम में खेल रहे हैं। इन खिलाड़ियों की मौजूदगी यह साबित करती है कि बिहार अब केवल प्रतिभा का स्रोत नहीं, बल्कि उसे निखारने वाला मजबूत मंच भी बनता जा रहा है।

ईशान किशन

वैभव सूर्यवंशी

मुकेश कुमार

आकाशदीप

शाकिब हुसैन

मोहम्मद इजहार

सार्थक रंजन

भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत

ईशान किशन को शुरुआती दिनों में क्रिकेट का गुर सिखाने वाले एनआईएस कोच मनीष कुमार ने कहा कि आईपीएल में बिहार के आठ खिलाड़ियों का एक साथ खेलना आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। यह संदेश भी साफ है कि अगर प्रतिभा और मेहनत हो, तो संसाधनों की कमी भी राह नहीं रोक सकती।

> ऐसे खिलाड़ियों पर लगातार नजर रखी जा रही है जो घरेलू टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उन्हें आगे बढ़ाया जाता है ताकि आईपीएल जैसा बड़ा मंच उन्हें मिल सके।
>
> **-जियाउल आरफिन,** बीसीए सचिव

Hindustan Page No-20

अपने खिलाड़ियों की भी सुध लेनी चाहिए

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी का भारत दौरा अच्छा था, पर हमें पंजाब फुटबॉल क्लब के निदेशक की बातों पर भी गौर करना चाहिए। मीडिया खबरों की मानें, तो उन्होंने यह कहा कि अगर मेसी के किसी दौरे पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय यह राशि भारतीय फुटबॉल की तरक्की में लगाई जाती, तो देश में ही 10 मेसी तैयार हो जाते। उनके अनुसार, असली जरूरत विदेशी सितारों की नहीं, बल्कि मजबूत और टिकाऊ फुटबॉल तंत्र बनाने की है। वाकई, सही योजना, आधुनिक कोचिंग और बेहतर बुनियादी ढांचे की तरफ ध्यान दिया जाए, तो भारत में भी मेसी जैसे विश्वस्तरीय खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं। वैसे भी, अपने देश में फुटबॉल को लेकर दीवानगी कम नहीं है। कई उम्दा खिलाड़ी यहां मौजूद हैं, जिनकी मदद ली जा सकती है। यदि जमीनी स्तर पर निवेश किया जाए, तो यहां के लड़के-लड़कियां फुटबॉल को एक बेहतर विकल्प के रूप में देख सकेंगे। अभी होता यह है कि बाजार के कारण क्रिकेट का बोलबाला है। नतीजतन, बच्चे भी क्रिकेट की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि फुटबॉल जिस तरह का खेल है, उसमें हम विश्व स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जाहिर है, फीफा विश्व कप जीतने का सपना केवल बड़े नामों को भारत बुलाने से साकार नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए मजबूत व्यवस्था भी बनानी होगी। हमें इस तरफ संजीदगी से ध्यान देना चाहिए।

सुजीत कुमार, टिप्पणीकार

मेसी को देखकर क्या मिलेगा, उसका खेल देखिए? वैसे, यह बात गलत नहीं जान पड़ती कि अगर घरेलू माहौल बेहतर बनाया जाए व युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाए, तो भारत भी फुटबॉल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी पैदा कर सकता है। जब सुविधाएं मिलती हैं, तो किस तरह हालात बदल जाते हैं, इसकी वानखे क्रिकेट है। इसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों की कतार लग गई है। इसको छोड़कर बाकी खेलों में शायद ही हमारे देश में बहुत कुछ सोचा जाता है। मेसी निश्चय ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें यहां लाकर जिस तरह से उनको नुमाइश की चीज बना दिया गया, वह गलत है। उनके इस दौरे पर जितनी राशि खर्च की गई है, वह घरेलू फुटबॉल की बेहतरी पर खर्च किए जा सकते थे। मेसी के दौरे में फुटबॉल प्रेमी कोलकाता की जनता ठगी गई। इसके लिए आयोजक जिम्मेदार हैं, मगर वे लोग भी समझदार तो नहीं ही हैं, जो मेसी को देखने के लिए दस-बीस हजार रुपये की टिकट लेकर वहां जुटे थे। हमें अपने देश के खेल माहौल को सुधारने पर निवेश करना चाहिए।

हितेंद्र पटेल, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

लियोनेल मेसी

सार्थक और मूल्यवान रहा मेसी का दौरा

महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने स्वदेश लौटने के बाद कहा- 'धन्यवाद भारत, उम्मीद है कि फुटबॉल में आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, और मैं फिर आऊंगा।' उनके मुंह से ये शब्द अनायास नहीं निकले हैं। मेसी का भारत में जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ, वह उनकी इस भावना में झलकता दिख रहा है। यह उनके प्रति दीवानगी ही थी कि उनके लिए फुटबॉलप्रेमियों ने हजारों रुपये खर्च किए। कुछ लोग ताना मार रहे हैं कि इतने पैसों में तो देश में ही कई मेसी पैदा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहने वाले भूल जाते हैं कि कोई यूं ही मेसी नहीं बनता। यह बनता है जुनून और निरंतर अभ्यास से। मेसी ने भारत आकर यही मूलमंत्र यहां के खिलाड़ियों को दिया है कि वे इस खेल को अपना जीवन बना लें। जब आप किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो फिर वह आपसे दूर नहीं रहता। वास्तव में, यही वह पड़ाव है, जहां हमें मेसी जैसे खिलाड़ियों के दौरों की अहमियत समझ में आती है। बेशक, उनकी इस यात्रा में काफी खर्च हुआ है, लेकिन इस तरह के खिलाड़ी जब हमारे बीच होते हैं, तो नई ऊर्जा हमारे अंदर भरते हैं। यह ऐसी ऊर्जा होती है, जो सही दिशा में बढ़ जाए, तो न सिर्फ हमारा जीवन सफल हो सकता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की साख भी बढ़ सकती है। माराडोना, पेले, रोनाल्डो, मेसी, रोनाल्डिन्हो, जैसे खिलाड़ी आपको प्रेरित करते हैं। यह आपको उल्लसित करते हैं। यह ऐसी संजीवनी देते हैं, जिसे आप रुपये-पैसों से नहीं तौल सकते। वह बहुमूल्य होती है। इसीलिए, मेसी के दौरे पर होने वाले खर्च को मुद्दा बनाने से हमें बचना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में फुटबॉल के विकास पर काम नहीं हो रहा है। नई उम्र के बच्चे लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस खेल के प्रशंसक पश्चिम बंगाल या केरल में नहीं, बल्कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार जैसे तमाम राज्यों में भी मिलेंगे। यहां तक कि गांव-देहातों तक में लड़कों को फुटबॉल खेलते हुए देखा जा सकता है। इस खेल को स्थानीय स्तर पर लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह सही है कि बुनियादी ढांचों के मामले में अभी काफी कुछ कमी है, लेकिन उनको भी दूर करने के प्रयास अनवरत किए जा रहे हैं। घरेलू टूर्नामेंट भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और उनमें प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिशें भी हो रही हैं। खुद भूटिया काफी सक्रिय हैं। ऐसे में, मेसी इन तमाम खिलाड़ियों के लिए 'माइटी कॉन्ड्रियां' जैसे हैं, जो उनके लिए 'जरूरी 'पावरहाउस' का काम करेंगे।

साकेत कुमार, टिप्पणीकार

Hindustan Page No-16

खेलों में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित कर रहा क्रिकेट

यहां स्कैन करें

शैलेश चतुर्वेदी | वरिष्ठ खेल पत्रकार

क्रिकेट का एक बड़ा चर्चित किस्सा है। जब कपिल देव नए-नए आए थे, उस दौर में कैंप में खाना 'सरकारी' होता था। कपिल देव ने तेज गेंदबाज होने के नाते ज्यादा और बेहतर खाने की मांग की, तो उन्हें मना करते हुए बताया गया कि इस देश में तेज गेंदबाज तो होते ही नहीं हैं। तब से लेकर बुधवार को आईपीएल की नीलामी तक क्रिकेट की दुनिया बदल चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने दो खिलाड़ियों- प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14.2-14.2 करोड़ रुपये में खरीदा है। दिल्ली टीम ने आकिब नबी दार को 8.4 करोड़ रुपये में खरीदा। ये नाम इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि आम जनता के लिए ये ज्यादा जाने-पहचाने नाम नहीं हैं। एक सीजन की यह रकम बताती है कि अनजान नाम भी कितना कमा सकते हैं। कपिल देव वाले 1977 के किस्से से लेकर 2025 तक क्रिकेट की दुनिया अलग मुकाम पर पहुंच गई है।

पैसा आता है, तो उम्मीदें लाता है, भरोसा लाता है। क्रिकेट ने यही काम किया है। कपिल देव समेत कुछ खिलाड़ी तो छोटी जगहों से आते रहे हैं, लेकिन पिछले दो-तीन दशकों से वह तादाद जिस तरह बदली है, उसने माहौल बदल दिया है। महानगरों के खेल से छोटे शहरों, कस्बों, गांवों का खेल बनने का लंबा सफर क्रिकेट ने तय किया है। इस तरह उसने क्रिकेट को लोकतांत्रिक ढांचे में बांध दिया है। मोहम्मद सिराज से लेकर नटराजन, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल... पूरी फेहरिस्त है। एक समय था, जब परिवार के बड़े पूछते थे कि खेल तो ठीक है, पर घर चलाने के लिए क्या करोगे? अब अगर आप खेलते हैं और एक स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो घर चलाने के लिए कोई समस्या नहीं आती। आईपीएल तो करोड़ों का खेल है। घरेलू क्रिकेट में भी ऐसे हालात हैं कि अगर राज्य टीम का हिस्सा बन गए, तो पैसों की कमी नहीं होगी।

क्रिकेट की डेमोक्रेसी दूसरे खेलों में भी पहुंच रही है। खेलों को अब जिस तरह का सहयोग सरकार से मिल रहा है, वह अनदेखा और अनजाना है।

80 के दशक का किस्सा है- एयरलाइंस में एक क्रिकेटर ने ग्राउंड ड्यूटी मांगी, तो उसे यह कहकर मना कर दिया गया कि प्राथमिकता हॉकी खिलाड़ी को दी जाएगी, क्रिकेटर को नहीं। क्रिकेट वहां से लेकर अगले 45-50 साल में इस जगह पहुंच गया है कि अब खिलाड़ियों को नौकरी की जरूरत ही नहीं है। जैसे नौकरी की जरूरत खत्म हुई है, वैसे ही छोटे कस्बों, गांवों से आने वाले खिलाड़ियों की मजबूरी भी खत्म हो गई है। अब बड़े शहर के संभ्रांत परिवार का बच्चा 'प्रिविलेज्ड' नहीं है, सबको समान अधिकार है। इसी ने क्रिकेट या यूं कहें कि खेलों में 'डेमोक्रेसी' लाने का काम किया है।

यह महिला क्रिकेट में भी हुआ है। एक समय महिला और पुरुष क्रिकेट बोर्ड अलग-अलग थे। फिर 'मर्जर' हुआ। दिन बदले, फीस मिलनी शुरू हुई। महिलाओं के लिए लीग शुरू हुई। स्मृति मंधाना जैसी खिलाड़ी को 'ब्रैंड एंडोर्समेंट' से भी पैसे मिलने शुरू हुए। महिला क्रिकेट टीम पिछले दिनों वर्ल्ड चैंपियन बन गई। इस बदलाव में वक्त लगा। बीसीसीआई के पिछले कुछ अध्यक्षों ने इस बदलाव की जरूरत को महसूस किया, खासतौर पर जय शाह ने, जिनके कार्यकाल में महिला क्रिकेट के लिए बहुत कुछ हुआ है।

क्रिकेट की डेमोक्रेसी दूसरे खेलों में भी पहुंच रही है। इन खेलों में सरकार की बेहद अहमियत है। जिस तरह का सहयोग सरकार से मिल रहा है, वह अनदेखा और अनजाना है। साथ में 'पर्सनल टच' भी है। इसे एक किस्से से समझा जा सकता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक पदक जीतकर लौटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना था। टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पीएमओ में अनुरोध भेजा कि उनका परिवार प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है। अगले दो-तीन घंटे में ही मिलने का कार्यक्रम तय हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीजेश के परिवार, खासतौर पर श्रीजेश के बेटे से उनके मिलने की तस्वीरें वायरल हुईं। रोचक बात है, जब श्रीजेश को पद्म भूषण मिला, तो प्रधानमंत्री ने उनसे बेटे के बारे में पूछा।

प्रधानमंत्री अगर खिलाड़ियों का, उनके परिवार का इस तरह ध्यान रखे, तो सरकारी तंत्र कैसे नहीं रखेगा? इस संजीदगी ने पूरे तंत्र को बदलने का काम किया है। सुविधाएं बढ़ी हैं। कई खेलों की लीग आई हैं। हालांकि, अब भी उन खेलों को सरकारी सहयोग से हटकर क्रिकेट की तरह अपना मुकाम बनाने की जरूरत है। अब कम से कम एक राह दिखने लगी है। अब ऐसा नहीं है कि नेशनल टीम में जगह नहीं मिलेगी, तो खिलाड़ी के लिए जिंदगी का रास्ता बंद दिखने लगेगा। उसके रास्ते खुले हैं, जिसने खेलों के लोकतंत्र को बनाया या बढ़ाया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Useful For Mains

आश्चर्य का परिवेश

तनुजा चौबे

मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं, जब वह अचानक किसी घटना या व्यवहार से अचंभित हो उठता है। अचंभा दरअसल बाहरी परिस्थितियों से जुड़ा होता है। जब कोई असंभव-सा कार्य पूरा हो जाए या अप्रत्याशित घटना घट जाए, तब मनुष्य का मस्तिष्क कुछ क्षण के लिए शून्य हो जाता है और प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। यही अचंभा है। यह अनुभव क्षणिक होता है और समय के साथ समाप्त भी हो जाता है। इसके विपरीत, आश्चर्य का संबंध मनुष्य के भीतर से है। यह मन की गहराई में जन्म लेता है और स्थायी रहता है। वास्तव में अचंभा ही आश्चर्य की भूमि तैयार करता है। जब कोई अचंभित करने वाली घटना हमें सोचने, समझने और जिज्ञासु बनने की दिशा में प्रेरित करती है, तभी वह आश्चर्य का रूप लेती है।

अचंभा केवल चौंकाता है, जबकि आश्चर्य हमें आत्मचिंतन और परिपक्वता की ओर ले जाता है। आश्चर्य मनुष्य की जिज्ञासा को जगाता है और उसे नई दृष्टि देता है। यह आंतरिक अनुभव हमें ज्ञान, सौंदर्यबोध और रचनात्मकता की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अचंभा क्षणिक प्रतिक्रिया है, जबकि आश्चर्य स्थायी अनुभूति। अचंभित होना जीवन की यात्रा का प्रारंभिक पड़ाव है और उसी के सहारे मनुष्य गहरे आश्चर्य तक पहुंचता है। आखिर यही आश्चर्य हमें नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

जब कोई मनुष्य लंबी जीवन-यात्रा से गुजरता है, तभी वह अपनी गहराई तक पहुंच पाता है। इस यात्रा में खोजने की प्रवृत्ति जन्म लेती है और यही प्रवृत्ति उसे आश्चर्य की अनुभूति कराती है। यह आश्चर्य मनुष्य को निरंतर खोज, गहन अध्ययन और जानने की इच्छा की ओर अग्रसर करता है। जब मनुष्य किसी सत्य से परिचित होता है, तो उसे आश्चर्य होता है, और उसी से प्रसन्नता की अनुभूति भी होती है। मगर कभी-कभी कोई दुखद घटना भी घट जाती है। इस तरह, सुख और दुख- दोनों भावों की तीव्रता से आश्चर्य की उत्पत्ति होती है।

खुशी से उपजा आश्चर्य मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। वहीं से भावनाओं का आवेग, ढकी-छिपी यादें और आत्मचिंतन की प्रक्रिया आरंभ होती है। अचानक प्राप्त हुई खुशी शरीर की स्थिति तक को प्रभावित कर देती है- कभी आंसुओं के रूप में, तो कभी हृदय की धड़कनों की गति बढ़ाकर। ऐसे क्षण शब्दविहीन हो जाते हैं, पर मन की गहराई तक पहुंचते हैं। यही खुशियां धीरे-धीरे हमारे भीतर समा जाती हैं, जिन्हें हृदय और मस्तिष्क से अलग करना कठिन हो जाता है।

मनुष्य का अचंभित या आश्चर्यचकित होना केवल किसी व्यक्तिगत घटना तक सीमित नहीं रहता। यह उसके अनुभवों, स्मृतियों और परिवेश से भी गहराई से जुड़ा होता है। जब कोई सुंदर परिदृश्य हमारी आंखों के सामने आता है, या कोई घटना घटती है, या कोई मधुर गीत और संगीत हमारे कानों को छूता है और हृदय को स्पर्श करता है, तब भी मन में वही आश्चर्य और भावनाओं का संयोग उत्पन्न होता है। यह अनुभव हमारे दृष्टिकोण को विस्तारित करता है, भावनात्मक संवेदनाओं को गहरा करता है और जीवन के छोटे-बड़े अनुभवों के प्रति हमारी समझ और सहानुभूति को बढ़ाता है।

जैसे ईश्वर की प्रार्थना, समाज-सेवा, आध्यात्मिक खोज, ध्यान और योग- ये सब कारक एक आस्थावान व्यक्ति को प्रसन्नता का भाव देते हैं। इन्हीं के माध्यम से उसे उस आंतरिक ऊर्जा का अनुभव होता है, जो ब्रह्मांड निरंतर सब तक पहुंचा रहा है। यह अनुभूति स्वयं में आश्चर्यजनक होती है और व्यक्ति को आगे खोजने की प्रवृत्ति तथा कार्य करने का उत्साह देती है। परिणामस्वरूप जीवन सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगता है।

दुनिया मेरे आगे

> मनुष्य का अचंभित होना केवल किसी व्यक्तिगत घटना तक सीमित नहीं रहता। यह उसके अनुभवों, स्मृतियों और परिवेश से भी गहराई से जुड़ा होता है। जब कोई सुंदर परिदृश्य हमारी आंखों के सामने आता है और हृदय को स्पर्श करता है, तब भी मन में वही आश्चर्य और भावनाओं का संयोग उत्पन्न होता है।

इसके विपरीत, अचानक आया दुख भी मनुष्य को आश्चर्य में डाल देता है। सुख और दुख दोनों ही आश्चर्य मस्तिष्क पर समान रूप से असर डालते हैं। आंसू वहां भी निकलते हैं, और हृदय की धड़कन वहां भी तेज हो जाती है। फर्क बस इतना है कि दुख का आश्चर्य मनुष्य को भीतर आत्मसात करने के बजाय बाहर की ओर धकेल देता है। यह नकारात्मकता उत्पन्न करता है, और इसी कारण कोई भी दुख की खोज नहीं करना चाहता।

इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने अंतर्मन में उतरकर दोनों प्रकार के आश्चर्यों में संतुलन बनाए। जीवन चक्र में सुख और दुख दोनों ही विस्मित करने वाले भाव होंगे और दोनों ही हमारे अनुभवों का हिस्सा होंगे। पर सच्ची खुशी तभी प्राप्त होती है, जब हम इन दोनों से ऊपर उठकर ध्यान, योग, अध्यात्म और प्रकृति से जुड़ते हैं। जब हम किसी भी विद्या से संबंध बनाकर अपने भीतर के कलुषित भावों को दूर करते हैं, छोटे-बड़े का भेद मिटाकर जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाते हैं, तब हम सच्ची आंतरिक प्रसन्नता को पा सकते हैं। आखिर जब मनुष्य त्याग और धैर्य के साथ जीता है, तब वह देखता है, आश्चर्य करता है कि बहुत कुछ छोड़कर ही सब कुछ पाया जा सकता है। यही भाव मनुष्य को आश्चर्य से भर देता है और आत्मानुभूति के अंतिम पड़ाव तक पहुंचा देता है।

डिजिटल संचार में भविष्य की भाषा

संस्कृत का वाक्य-विन्यास गणितीय रूप में इतना सुसंगत है कि इसे एक 'संगणक अनुकूल भाषा' माना जाने लगा है। इसकी सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स के क्षेत्र को और सार्थकता मिल सकती है।

प्रमोद भार्गव

एक समय जब संगणक के बढ़ते प्रभाव और 'कमांड लैंग्वेज' (समादेश-भाषा) अंग्रेजी होने के कारण इसे हिंदी के लिए व्यवधान माना जा रहा था, ठीक उसी समय 'फोर्ब्स पत्रिका' ने एक रपट में यह तथ्य स्थापित किया था कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। यह दुनिया की सबसे तर्कसंगत और व्याकरणीय दृष्टि से वैज्ञानिक भाषा है। साथ ही, इसे हिंदी, मैथिली, उर्दू, ओड़िया, बांग्ला, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, बुंदेली, अवधी और बृज इत्यादि सभी आधुनिक एवं मूर्त भाषाओं तथा बोलियों की जननी भी माना जाता है। इधर, जैसे-जैसे दुनिया बहु-सांस्कृतिक पहचान और अंकीय यानी डिजिटल संचार से जुड़े ज्ञान को समझ रही है, संस्कृत उसी के समांतर भविष्य की भाषा के बेहतर विकल्प के रूप में उभर रही है। संस्कृत की भाषाई सटीकता और तार्किकता के कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसी प्रौद्योगिकी के नवीनतम क्षेत्रों में इसके प्रयोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसे कंप्यूटर की भाषा बनाने में नासा और मुंगेर स्थित योग विश्वविद्यालय अहम योगदान दे रहे हैं।

संस्कृत की व्याकरण प्रणाली को तीन हजार से भी अधिक वर्ष पहले महर्षि पाणिनि ने संहिताबद्ध किया था। वैज्ञानिक इसे भाषा विज्ञान का एक अद्वितीय उदाहरण मानते हैं। पाणिनि का व्याकरण संस्कृत भाषा के लिए रचित 'अष्टाध्यायी' नामक ग्रंथ पर आधारित है, जिसमें लगभग चार हजार सूत्र हैं। यह व्याकरण अत्यधिक वैज्ञानिक है। इसने संस्कृत को मानकीकृत किया। पाणिनि की यह पद्धति दुनिया की पहली औपचारिक विधि मानी जाती है। इसे सहायक प्रतीकों (प्रत्यय) की प्रणाली ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। अब भारत, अमेरिका और जर्मनी सहित कई देशों के तकनीकी एवं भाषा वैज्ञानिक पाणिनि के संस्कृत सूत्रों से एक गणितीय सूत्र तैयार कर रहे हैं, जो कंप्यूटर को सरलता से समझ में आ जाए। यह परिवर्तनकारी शोध कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में चल रहा है। इसे विकसित कर लिए जाने के बाद पाणिनि के सूत्रों से कंप्यूटर को पहली प्राकृतिक भाषा मिल जाएगी, जिसका उपयोग नासा की प्रयोगशाला से लेकर दुनिया की अधिकांश प्रयोगशालाओं में होगा। फिर दुनिया कंप्यूटर की वर्तमान कृत्रिम भाषा से मुक्त हो जाएगी। पाणिनि के सूत्रों का अध्ययन कर दुनिया के वैज्ञानिक अचंभित हैं कि लगभग ढाई हजार वर्ष पहले पाणिनि ने कैसे इतने शुद्ध एवं संक्षिप्त सूत्र विकसित किए होंगे!

व्याकरण के ये सूत्र एकदम कंप्यूटर की भाषा 'कोबोल' और 'फोरट्रान' से मिलते-जुलते हैं। 'कोबोल' यानी 'कामन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज'। यह एक अंग्रेजी जैसी 'प्रोग्रामिंग' भाषा है, जिसे व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किया गया। 'फोरट्रान' यानी 'फार्मूला ट्रांसलेशन' है। यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसे जान बैकस और उनके सहयोगियों ने 1957 में आइबीएम में विकसित किया था। इसका मुख्य लक्ष्य गणितीय सूत्रों को कंप्यूटर कोड में बदलना था, जो इसे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए उपयुक्त बनाता है। अंग्रेजी में बड़ी संख्या में शब्दों का उच्चारण एवं अर्थ अस्पष्ट एवं भिन्न होते हैं। जैसे चाचा, मामा और मौसा के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है- 'अंकल'। इसी तरह 'बैंक' शब्द धन के लेन-देन की

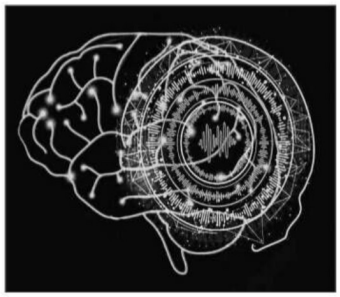

संस्था से जुड़ा है, किंतु नदी के किनारे को भी 'बैंक' कहा जाता है। ऐसे शब्द भ्रम पैदा करते हैं। वैज्ञानिक भाषा उस प्राकृतिक भाषा को मानते हैं, जिनमें भ्रम और दोहरे अर्थ नहीं होते। जिन भाषाओं में ऐसा होता है, उन्हें कृत्रिम भाषा माना गया है। पाणिनि के व्याकरण ने संस्कृत को पूर्ण, स्पष्ट, संक्षिप्त एवं सूत्रबद्ध किया है। अमेरिका, जर्मनी और भारत सहित कई देशों के वैज्ञानिक पाणिनि के संस्कृत सूत्रों से एक गणितीय सूत्र तैयार कर रहे हैं।

> **आज शिक्षा का स्वरूप रोजगार को ध्यान में रख कर विकसित किया जा रहा है। इसलिए विद्यालयों में वही भाषाएं पढ़ाने पर विचार किया जाता है, जिनसे विद्यार्थियों के काम-धंधे के उत्तम अवसर मिल सकें। संस्कृत कंप्यूटिंग की भाषा में उपयोगी साबित हो जाती है, तो डिजिटल भारत की भाषा संस्कृत हो ही जाएगी, भारतीय भाषाओं को भी डिजिटल भाषाएं बनने में देर नहीं लगेगी। संस्कृत ज्ञान, मूल्य और विज्ञान का सूत्र स्रोत मानी जाती रही है। अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने संस्कृत के प्राचीन साहित्य को प्रेरणा स्रोत माना है। इसलिए कंप्यूटर की भाषा विकसित करने के लिए संस्कृत को माध्यम बनाया जा रहा है।**

ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा मिल जाएगी और दुनिया कृत्रिम भाषा के भ्रमों से मुक्त हो जाएगी।

संस्कृत का वाक्य-विन्यास गणितीय रूप में इतना सुसंगत है कि इसे एक 'संगणक अनुकूल भाषा' माना जाने लगा है। इसकी सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स के क्षेत्र को और सार्थकता मिल सकती है। भारत में प्रौद्योगिकी शैक्षणिक संस्थान कंप्यूटिंग और एआइ अनुसंधान में संस्कृत को शामिल कर रहे हैं। इन अनुसंधानों के पूरा होने पर संस्कृत, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार की भाषा बन जाएगी। आज शिक्षा का स्वरूप रोजगार को ध्यान में रख कर विकसित किया जा रहा है। इसलिए विद्यालयों में वही भाषाएं पढ़ाने पर विचार किया जाता है, जिनसे विद्यार्थियों के काम-धंधे के उत्तम अवसर मिल सकें। संस्कृत कंप्यूटिंग की भाषा में उपयोगी साबित हो जाती है, तो डिजिटल भारत की भाषा संस्कृत हो ही जाएगी, भारतीय भाषाओं को भी डिजिटल भाषाएं बनने में देर नहीं लगेगी। संस्कृत ज्ञान, मूल्य और विज्ञान का सूत्र स्रोत मानी जाती रही है। पहले परमाणु विस्फोट से लेकर अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने संस्कृत के प्राचीन साहित्य को प्रेरणा स्रोत माना है। इसलिए कंप्यूटर की भाषा विकसित करने के लिए संस्कृत को माध्यम बनाया जा रहा है।

विज्ञान के नए शोध भारतीय एवं पश्चिमी विधियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में जब सुपर कंप्यूटर नहीं था, तब अमेरिका से इसकी तकनीक की मांग की गई थी, लेकिन उसने 1987 में इस तकनीक को देने से साफ मना कर दिया था। देश के पहले सुपर कंप्यूटर 'परम' के निर्माता और सुपर कंप्यूटिंग की शुरुआत से जुड़े विजय पांडुरंग भटकर ने इसे एक चुनौती माना और इसके आविष्कार में लग गए। उनके नेतृत्व में 'सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस कंप्यूटिंग' (सी-डीएसी) द्वारा 1991 में विकसित कर लिया गया। इस सुपर कंप्यूटर और सी-डेक के आविष्कार को भारत की एक बड़ी उपलब्धि माना गया। इसी संस्था ने देश का पहला सुपर कंप्यूटर 'परम-8000' विकसित किया। इसके बाद 'परमसिद्धि-एआइ' नामक सुपर कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग सफलतापूर्वक शुरू हुआ। यह भारत का पहला द्रुत गति का सुपर कंप्यूटर था। नवंबर-2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 500 सर्वाधिक क्षमता वाले सुपर कंप्यूटरों में भारत के चार कंप्यूटर शामिल हैं। ये हैं- ऐरावत-पीएसएआइ, परमसिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर।

कण-यांत्रिकी को कंप्यूटर का भविष्य माना जा रहा है। पारंपरिक कंप्यूटर बिट (अंश) पर काम करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में प्राथमिक इकाई 'क्यूबिट' यानी कणांश होता है। पारंपरिक कंप्यूटर में प्रत्येक बिट का मूलाधार या मूल्य शून्य और एक (एक) होता है। कंप्यूटर इसी शून्य और एक की भाषा में कुंजी-पटल (की-बोर्ड) से दिए निर्देश को ग्रहण करके समझाता है और परिणाम को अंजाम देता है। वहीं क्वांटम की विलक्षणता यह होगी कि वह एक साथ ही शून्य और एक दोनों को ग्रहण कर लेगा। यह क्षमता क्यूबिट की वजह से विकसित होगी। परिणामस्वरूप यह दो क्यूबिट में एक साथ चार मूल्य या परिणाम देने में सक्षम हो जाएगा। एक साथ चार परिणाम स्क्रीन पर प्रकट होने की इस अद्वितीय क्षमता के कारण इसकी गति पारंपरिक कंप्यूटर से कहीं ज्यादा होगी। इस कारण यह पारंपरिक कंप्यूटरों में जो गूढ़-लेखन कर दिया जाता है, उससे कहीं अधिक मात्रा में यह कंप्यूटर डेटा ग्रहण करने और सुरक्षित रखने में समर्थ होगा।

Jansatta Page No-6

रूपरेखा तैयार

प्राकृतिक आपदा से निपटने की गृह मंत्री शाह के आह्वान को धरातल पर उतारेगा पंचायतीराज मंत्रालय, देशभर के 81 संवेदनशील जिलों से चिन्हित किए जाने हैं गांव, दो वर्ष की कार्ययोजना पर खर्च होंगे 507.37 करोड़ रुपये

आपदा प्रबंधन में माडल बनेंगे 20 राज्यों के 20 गांव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भौगोलिक परिस्थितियों के कारण देश के अलग-अलग राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। इनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) सक्रिय रहते हैं, पर गृह मंत्री अमित शाह ने विजन दिया कि जो गांव बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, तट क्षरण व नदियों के कटाव जैसी छह प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। यदि उसी पहले मोर्चे पर तैयारी मजबूत की जाए तो बेहतर होगा।

गृह मंत्री के इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय और एनडीएमए ने विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत ऐसी परिस्थितियों से जूझने वाले 20 राज्यों में एक-एक गांव को आपदा प्रबंधन के माडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।

गृह और पंचायतीराज मंत्रालय ने इस दो वर्षीय कार्यक्रम को इस उद्देश्य के साथ तैयार किया है कि आपदा के बाद इससे निपटने के स्थान पर आपदा से पहले ही बचाव व जोखिमों को कम से कम करने की तैयारी गांव स्तर पर कर ली जाए। इसके तहत 20 राज्यों में प्राकृतिक आपदा के मामले में संवेदनशील 81 जिलों को कार्ययोजना में शामिल किया गया है। इसके दायरे में कुल 1620 ग्राम पंचायतें आ रही हैं।

केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य स्वयं चिन्हित करें कि उनके क्षेत्र में जिस आपदा की आशंका सबसे अधिक रहती है, उसकी तैयारी के लिए एक गांव को माडल के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित करें। इसके बाद चिन्हित गांव की ग्राम पंचायत विकास योजना में संबंधित आपदा के प्रबंधन का एकीकरण किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण की योजना है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे सरपंच व अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण, पंचायत कार्यकर्ताओं के लिए कौशल विकास, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों के साथ सीधा जुड़ाव, सामुदायिक स्वयंसेवकों (आपदा मित्रों) तैयार करना, एनसीसी, एनएसएस के माध्यम से युवा संगठन तैयार करना, बहुस्तरीय शमन रणनीति आदि को शामिल किया जाएगा। यह दो वर्ष का कार्यक्रम वर्ष 2027 तक चलेगा, जिसमें बीस माडल गांव देशभर में तैयार हो जाएंगे। वह जिस कुशलता से आपदा से निपटेंगे, उसका अनुकरण देश के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए गत दिवस उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह कुल 507.37 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति दे चुके हैं।

****

राज्य	चिन्हित जिले	आपदा प्रबंधन
उत्तर प्रदेश	छह	भूकंप या बाढ़
केरल	छह	तटीय क्षरण
ओडिशा	छह	चक्रवात या सूखा
असम	छह	बाढ़
महाराष्ट्र	छह	सूखा या भूकंप
राजस्थान	छह	सूखा या बाढ़
तमिलनाडु	पांच	चक्रवात या सूखा
बिहार	पांच	भूकंप या बाढ़
गुजरात	पांच	भूकंप या बाढ़
हिमाचल प्रदेश	तीन	बाढ़ या भूस्खलन
उत्तराखंड	तीन	बाढ़ या भूस्खलन
अरुणाचल प्रदेश	तीन	बाढ़ या भूस्खलन
सिक्किम	तीन	भूस्खलन
मेघालय	तीन	बाढ़ या भूस्खलन
कर्नाटक	तीन	सूखा या भूस्खलन
आंध्र प्रदेश	तीन	चक्रवात या भूस्खलन
पंजाब	दो	भूकंप या नदी का कटाव
नगालैंड	दो	भूस्खलन
मिजोरम	दो	बाढ़ या भूस्खलन

चीन की दुखती रग दबाने का समय

विजय क्रांति

चीनी आक्रामकता और धमकियों का सही जवाब यही होगा कि भारत सरकार तिब्बत पर चीन के अनैतिक कब्जे को चुनौती दे

अवधेश राजपूत

कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग में छठे दलाई लामा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में भागीदारी का निमंत्रण मिलने पर मैंने कई पत्रकार और राजनयिक मित्रों से कहा था कि वे चीन सरकार के गुस्से और तिलमिलाहट भरे बयान सुनने के लिए तैयार रहें। यह बात मैंने किसी भविष्यवक्ता होने के नाते नहीं, बल्कि तिब्बत और भारत के बारे में चीनी रवैये और नीतियों पर अपने पांच दशकों के अध्ययन के आधार पर कही थी। हुआ भी वैसा ही। तीन से छह दिसंबर तक चली इस कांफ्रेंस के तीन दिन बाद ही चीन सरकार ने तिब्बत के बारे में अपनी नीति बताने वाली वेबसाइट पर भारत सरकार, अरुणाचल के मुख्यमंत्री और इस कांफ्रेंस के खिलाफ जिस तरह की जहरीली प्रतिक्रिया व्यक्त की वह चीन सरकार के गुस्से, तिलमिलाहट और आक्रामकता की ही अभिव्यक्ति थी कि उसे सही जगह चोट पहुंची है।

चीनी सरकार के एक टिप्पणीकार के बयान में अरुणाचल के लिए न केवल चीनी नाम 'झांगमान' और तिब्बत के लिए 'शीझांग' का इस्तेमाल किया गया, बल्कि इस क्षेत्र को 'दक्षिणी तिब्बत' बताते हुए कांफ्रेंस को 'दक्षिण-पूर्वी चीन' के हिस्से पर भारत सरकार की ओर से किया गया 'सांस्कृतिक अतिक्रमण' तक बता दिया। हालांकि भारत पर ऐसे आरोप लगाते हुए चीन सरकार इस सच्चाई को पूरी तरह निगल गई कि अरुणाचल प्रदेश को 'दक्षिणी तिब्बत' बताकर उस पर अपना अधिकार जताने के पीछे उसकी एकमात्र दलील केवल यही है कि चीन 1951 से तिब्बत पर गैर-कानूनी और औपनिवेशिक कब्जा जमाए बैठा है। दुर्भाग्य से नेहरू काल से लेकर आज तक अरुणाचल प्रदेश और देश की हिमालयी सीमा पर चीनी आक्रामकता सहता आ रहा है। किसी भी सरकार ने यह साहस नहीं दिखाया कि वह तिब्बत पर चीन सरकार के गैरकानूनी कब्जे को चुनौती देकर इस विवाद की असली जड़ पर हमला करे।

हाल में आयोजित कांफ्रेंस के आयोजन के पीछे मूल कारण छठे दलाई लामा ग्यालवा त्सांगयांग ग्यात्सो के ऐतिहासिक महत्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करना था। छठे दलाई लामा इस मायने में अनूठे थे कि उनका जन्म एक मार्च, 1683 के दिन तिब्बत से बाहर भारत के तवांग क्षेत्र (अरुणाचल) में हुआ था। संयोग से तिब्बत पर 1951 के चीनी कब्जे और बाद में 1959 में चीनी सेना के हाथों पकड़े जाने या हत्या किए जाने के डर से भागे हुए 14वें दलाई लामा ने जब भारत में शरण ली तब तवांग के रास्ते ही भारत में प्रवेश किया था। इसलिए तिब्बत के दो दलाई लामाओं के साथ गहरे संबंध के कारण ही तवांग का विशेष महत्व है। कांफ्रेंस को तवांग में आयोजित किए जाने का भी यही कारण रहा। चीन इससे परेशान है कि इस कांफ्रेंस में भारत और तिब्बत के अलावा अमेरिका, जापान, मंगोलिया, इजरायल, कनाडा समेत कई देशों के नामी गिरामी तिब्बत-विशेषज्ञों, चीनी मामलों के जानकार और बौद्ध धर्म के विद्वानों ने हिस्सा लिया। चीन सरकार के लिए हताशा और तिलमिलाहट का एक कारण यह भी था कि इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन (आइबीसी) ने अरुणाचल सरकार के कार्मिक एवं आध्यात्मिक विभाग के माध्यम से किया।

आइबीसी को लेकर चीन सरकार की सबसे बड़ी छटपटाहट यह है कि भारत के इस संस्थान ने दो दशकों से चल रहे उन चीनी प्रयासों पर पानी फेर दिया है, जिनका लक्ष्य तिब्बत में अपनी उपस्थिति को आधार बनाकर चीन को 'वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम' (डब्ल्यूबीएफ) के माध्यम से चीन को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध जगत का सर्वोच्च और एकमात्र प्रतिनिधि स्थापित करना है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सत्ता में आने के बाद ही इस अभियान को लेकर अपनी साख दांव पर लगा दी। चीन को वैश्विक बौद्ध समाज का एकमात्र नेतृत्वकर्ता स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति शी भारत में रहने वाले दलाई लामा को दरकिनार कर चीन के कठपुतली पंचेन लामा ग्यालसेन नोरबू को दुनिया का सर्वोच्च बौद्ध नेता स्थापित करने की पुरजोर कोशिशें करते आए हैं। यह बात अलग है कि स्वयं तिब्बती जनता द्वारा ठुकरा दिए गए नोरबू को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धर्मगुरुओं और विद्वानों के बीच मान्यता नहीं मिल पाई है। दूसरी ओर भारत के आइबीसी ने अपने कई प्रभावशाली आयोजनों के माध्यम से दुनिया भर के वरिष्ठ बौद्ध धर्मगुरुओं को संगठित करने और उन्हें एक मंच पर लाकर भारत को वैश्विक बौद्ध नेतृत्व के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पिछले कई वर्षों से अगले दलाई लामा के अवतार का चुनाव करने पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार के प्रयासों को इस साल जुलाई में आइबीसी के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में दुनिया भर से आए बौद्ध धर्मगुरुओं ने सिरे से ठुकरा दिया था।

तवांग कांफ्रेंस के खिलाफ अपने इस तल्खी भरे बयान से एक पखवाड़ा पहले ही चीन ने अरुणाचल की एक भारतीय महिला यात्री को एक चीनी हवाई अड्डे पर महज इस आधार पर अपमानित और परेशान किया था कि उनका पासपोर्ट भारतीय है। चीन का कहना था कि अरुणाचल पर चीनी दावे के हिसाब से उनके पास 'चीनी पासपोर्ट' होना चाहिए था। उससे भी पहले दर्जनों बार चीन सरकार अरुणाचल के खिलाड़ियों को चीनी वीजा देने से इन्कार कर चुकी है। उसने भारतीय राष्ट्रपति से लेकर दलाई लामा की अरुणाचल यात्राओं का भी विरोध किया है। इस बार भी चीनी टिप्पणी में बार-बार छठे दलाई लामा का जन्मस्थान होने के आधार पर अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताने का प्रयास किया गया है। ऐसे में चीन की आक्रामकता और धमकियों का सही जवाब यही होगा कि भारत सरकार तिब्बत पर चीन के गैरकानूनी और अनैतिक कब्जे को चुनौती देकर चीन की खुराफातों की दुखती रग को दबाने का काम करे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो चीन को गलत संदेश जाएगा।

(लेखक तिब्बत-चीन मामलों के विशेषज्ञ और सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड ऐगेजमेंट के चेयरमैन हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

पुराने रिश्तों को नई अहमियत देता भारत

तलमीज अहमद | पूर्व राजनयिक

प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा उल्लेखनीय रही, उन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया है, अब अधिकारियों को आगे कदम बढ़ाना है।

तीन देशों (जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान) की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को निकल रहे थे, तब उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इन देशों के साथ सभ्यतागत संबंधों के साथ-साथ व्यापक समकालीन द्विपक्षीय रिश्ते होने के कारण उनका दौरा सुखद रहेगा। कमोबेश ऐसा ही हुआ दिख रहा है। उनकी यह यात्रा उल्लेखनीय मानी जाएगी, क्योंकि पहली बार जॉर्डन और इथियोपिया को हमने इतना महत्व दिया है, जबकि ओमान के साथ अपने पुराने रिश्ते में नई जान फूंकने की गंभीर कोशिश की है।

यह सही है कि अब किसी भी यात्रा की सफलता द्विपक्षीय समझौते या एमओयू से आंकी जाने लगी है, लेकिन मेरा मानना है कि समझौते तो महज पहली सीढ़ी होते हैं। रिश्तों की बुनियाद उन संधियों को अमल में लाने से मजबूत बनती है। ऐसी यात्राओं से प्रधानमंत्री रास्ता दिखाते हैं, मगर उन पर आगे बढ़ने का काम अधिकारियों को करना होता है। दुखद है कि जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के मामले में हमसे यह चूक हो गई और अहम होने के बावजूद हमने इन देशों को पिछले कुछ दशक में पर्याप्त महत्व नहीं दिया था।

जॉर्डन का हमारे लिए काफी सामरिक महत्व है, क्योंकि यह पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है और पांच अरब देशों और इजरायल से उसकी सीमा लगती है। गौरतलब यह भी है कि जॉर्डन अपने अकाबा बंदरगाह के कारण लाल सागर से जुड़ा हुआ है। यह देश तीन वजहों से हमारे लिए अहमियत रखता है- पहली, वह फॉस्फेट का बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जिसका इस्तेमाल खाद-उर्वरकों में होता है। दूसरी- वहां हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जाते हैं और तीसरी- नौसैन्य सहयोग के लिहाज से, जिसे हमने अब तक बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में अक्षय ऊर्जा, जल संसाधन प्रबंधन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, डिजिटल सॉल्यूशन जैसे क्षेत्रों में पांच एमओयू पर दस्तखत किए गए और द्विपक्षीय व्यापार को अगले पांच साल में पांच अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया, मगर इनके साथ-साथ हमें अपनी 'महासागर' नीति पर भी मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें जॉर्डन हमारी काफी मदद कर सकता है। अभी हमें हिंद महासागर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसकी दो महत्वपूर्ण नदियां हैं- फारस की खाड़ी और लाल सागर। लिहाजा लाल सागर में जॉर्डन की उपस्थिति को देखते हुए हमें उसके साथ नौसैन्य सहयोग पर खासा ध्यान देना चाहिए। इससे हमारे कई हित सध सकेंगे।

इथियोपिया की बात करें, तो यह वह मुल्क है, जहां पिछली सदी के 50 और 60 के दशक में हिन्दुस्तान से कई शिक्षक जाते थे। वहां की दो पीढ़ियों ने भारतीय शिक्षकों से ही पढ़ाई की है। मगर बाद में, क्षेत्रीय तनाव के साथ ही अन्य वजहों से इस रिश्ते पर ग्रहण लग गया, जबकि कई कारणों से यह देश हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। यह सही है कि लाल सागर या किसी अन्य समुद्र से इसका सीधा जुड़ाव नहीं है, लेकिन यह प्राकृतिक संसाधनों से धनी है और नील नदी जैसी बहुमूल्य संपदा भी इसके पास है। इतना ही नहीं, सुरक्षित लाल सागर के लिए 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' की भी काफी अहमियत है, जिसमें सूडान, सोमालीलैंड, जिबूती, इरिट्रिया के साथ इथियोपिया शामिल हैं। जो लोग नहीं जानते, उनको बताते चलें कि लाल सागर से हमारा करीब 200 अरब डॉलर का माल गुजरता है। वैश्विक व्यापार का 12 फीसदी निर्यात भी यहीं से होता है। यह एशिया व यूरोप को भी जोड़ता है। ऐसे में, भारत की 'महासागर' नीति में इथियोपिया एक अहम खिलाड़ी बन सकता है। लिहाजा, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा पुरानी गलतियों से उबरने की कोशिश मानी जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी को 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से भी सम्मानित किया गया, हालांकि हमें इससे आगे की राह बनानी चाहिए। इथियोपिया के संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से अच्छे संबंध हैं और यूएई से हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। आज यमन के बंदरगाह, लाल सागर, अदन की खाड़ी पर अमीरात का खासा प्रभाव है, साथ ही सोमालीलैंड और इथियोपिया में उसकी अच्छी मौजूदगी है। ऐसे में, हम संयुक्त अरब अमीरात को जोड़कर इथियोपिया के साथ त्रिपक्षीय रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी, अमीरात के पास काफी ज्यादा संसाधन हैं, मगर अपनी नौसेना नहीं, जबकि भारत के पास एक बड़ी नौसैन्य ताकत है। अमीरात की सैन्य जरूरतें पूरी करके हम इस त्रिगुट को मजबूत बना सकते हैं।

ओमान का मामला जॉर्डन व इथियोपिया से अलग है। मस्कट के साथ हमारा रिश्ता तकरीबन 5,000 साल पुराना है। वह भी ऐसा, जिसमें अब तक कोई परेशानी नहीं आई है। फिर भी, हमारी तरफ से उदासीनता बरती गई। प्रधानमंत्री की यात्रा से इस रिश्ते में नई ऊर्जा मिली है। ओमान के साथ अच्छी बात यह भी है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ता है, जबकि यह वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का एक प्रमुख समुद्री जलमार्ग है। एशियाई देशों में आने वाले तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से गुजरते हैं। फिर, ओमान के कई बंदरगाह हिंद महासागर में हैं। सलालाह, सोहार, दुक्म, मस्कट जैसे उसके बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण हैं। यहां तो हमारी नौसेना की भी अच्छी मौजूदगी रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान हमने ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है, जिससे टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल जैसे कई क्षेत्रों में व्यापार में सुगमता आ सकेगी। फिलहाल, दोनों देशों के बीच करीब 12 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है और भारत मूलतः तेल, प्राकृतिक गैस, खाद-उर्वरक व पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है। माना जा रहा है, इसमें अब और तेजी आ सकती है।

साफ है, प्रधानमंत्री ने अच्छे नेतृत्व का परिचय देते हुए एक नई शुरुआत की है। अब इसे ठोस आधार देने का काम हमारे अधिकारियों के जिम्मे है। यह करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इन पर बड़ी ताकतों की भी नजर है। लिहाजा, प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल में हमारी सुस्ती हमें कूटनीतिक तौर पर पीछे धकेल सकती है। हमें इनकी अहमियत समझते हुए अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, जो सिर्फ बातचीत की मेज पर संभव नहीं। इसके लिए उन तमाम परियोजनाओं को जमीन पर आगे बढ़ाना होगा, जिसका वायदा हमने कर रखा है। इन देशों के साथ समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय आधार पर तकनीकी आदान-प्रदान संबंधी में मधुरता के महत्वपूर्ण अवसर हैं। इनके दीर्घकालिक सामरिक मूल्यों को देखते हुए हमें स्पष्ट नीति बना लेनी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Hindustan Page No-16